A Daily News Magazine
भोपाल
गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 108, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

अब गुजरात का कच्चा नारियल भी दक्षिण भारत पर भारी!

मनीषा मोंडल

भारत में एक नया नारियल हब तैयार हो रहा है। यह है गुजरात, जहां से हरे, कच्चे नारियल से भरे टेंपो रोज़ाना दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी जा रहे हैं। सोमनाथ, जूनागढ़, वलसाड़ और भावनगर से होकर गुजरने वाला एनएच-51 अब 'नारियल हाईवे' बन गया है। पिछले पांच सालों में यहां नारियल की खेती तेज़ी से बढ़ी है और किसानों का कहना है कि इस फल ने उन्हें पूरा फायदा दिया है। हरा, कच्चा, हल्की मिठास वाला नारियल अब इस तटीय इलाके की सबसे ज्यादा कमाई वाला फसल बन गया है।

सोमनाथ के किसान नारणभाई सोलंकी ने कहा, 'हमारे लिए नारियल कल्पवृक्ष है। यह हमारी जीवनरेखा बन गया है।' पिछले कुछ वक्त में, दो सितंबर का 'विश्व नारियल दिवस' गुजरात में एक उत्सव जैसा हो गया है। इस साल, राज्य के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने बताया कि 2014-15 में 22,451 हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 28,197 हेक्टेयर तक नारियल की खेती का क्षेत्र करीब 26 प्रतिशत बढ़ गया है। फिलहाल, गुजरात हर साल 260.9 मिलियन नारियल उगाता है, जिनमें से करीब 20 प्रतिशत कच्ची अवस्था में तोड़े जाते हैं। कुल उत्पादन में यह देश में सातवें स्थान पर है, लेकिन उत्तर भारत में इसका पूरा दबदबा है - यहां बिकने वाले नारियल का करीब 40 प्रतिशत गुजरात से आता है।

इस साल नारियल विकास बोर्ड के मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर पद से रिटायर हुए एस. जयकुमार ने कहा, 'आने वाले वर्षों में गुजरात दक्षिणी राज्यों से मुकाबला कर सकता है। देश में कच्चे नारियल की कमी है और गुजरात ने इस मौके को पकड़ लिया।'

उत्पादकों और उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तटीय गुजरात में नारियल उत्पादन एक दशक से बढ़ रहा है, लेकिन कोविड ने हरे नारियल की मांग को और बढ़ा दिया। देश भर के डॉक्टर मरीजों को पेप्सी-कोक की जगह नारियल पानी पीने की सलाह दे रहे थे और यह आदत लोगों में जम गई। नारियल पानी हेल्थ ड्रिंक बना, कीमतें स्थिर रहीं और तट के किसानों ने और पेड़ लगा दिए। पुरानी मुख्य फसल मूंगफली पीछे छूट गई। नारियल की कमाई पेड़ों जितनी ऊंची है - किसान कहते हैं कि एक बीघा से 50,000-70,000 रुपये की आमदनी हो जाती है, जबकि मूंगफली शायद ही कभी 30,000 रुपये पार करती थी। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान महाविद्यालय के प्रिंसिपल और डीन डॉ. डी.के. वरू के अनुसार सौराष्ट्र में नारियल का विस्तार किसी सरकारी योजना से नहीं शुरू हुआ। यहां किसानों ने सब कुछ खुद किया। नारियल विकास बोर्ड ने तो अब जाकर ऑफिस खोला है। गुजरात का कच्चा नारियल पानी देश में सबसे अच्छा है - दक्षिण से भी बेहतर।' उद्यान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस क्षेत्र में नारियल ने मूंगफली और गेहूं की 40-50 प्रतिशत खेती की जगह ले ली है। बाज़ार के सबसे बड़े सप्लायरों में से एक, सिद्धि सप्लायर्स के मालिक राजू भाई ने कहा, 'यह नारियल का ऑफ सीजन है, इसलिए सिर्फ सात-आठ ट्रक हैं। गर्मियों में मैंने एक दिन में 60 से ज्यादा ट्रक भरे हैं। दिल्ली में जो भी नारियल मिलता है, वह हम भेजते हैं।

अच्छी क्वालिटी का नारियल थोक बाज़ार में अभी 25 रुपये का है, लेकिन गर्मियों में 60 रुपये तक हो जाता है। किसानों को 10-15 रुपये मिलते हैं, पर ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा पैसा खा जाता है। दिल्ली-एनसीआर में एक नारियल 80-100 रुपये में बिकता है। राजू ने कहा कि पिछले साल उन्होंने 10 लाख रुपये से ज्यादा का लाभ कमाया।

पूर्वी भारत के नारियल का व्यापार अब उत्तर भारत में कम हो गया है और गुजरात उस जगह को भर रहा है। गुजरात को दक्षिण भारत पर भी बढ़त मिल रही है। राजू ने कहा, 'उत्तर के खरीदार गुजरात से नारियल लेना पसंद करते हैं, क्योंकि दक्षिण से लाने की तुलना में ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है। हालांकि चार दक्षिण भारतीय राज्य भारत के 91% नारियल उत्पादन करते हैं, लेकिन ICAR-CPCRI के निदेशक हेब्बार ने कहा कि गुजरात के पास अपनी जगह और बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। रिपोर्ट्स हैं कि गुजरात में कुल उत्पादन का 20% कच्चा नारियल है।इससे दक्षिण के कच्चे नारियल के बाज़ार पर असर पड़ेगा।' इसका उत्पादन मुख्य रूप से सात तटीय जिलों में है–गिर सोमनाथ, भावनगर, कच्छ, वलसाड, जूनागढ़, नवसारी और द्वारका, लेकिन कोकोनट बोर्ड के पूर्व अधिकारी जयकुमार कहते हैं कि और 15 हजार हेक्टेयर ज़मीन भी खेती में लाई जा सकती है।

कहते हैं कि गुजरात में नारियल उत्पादन में उछाल तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। अब राज्य सरकार के पास 'गुजरात कोकोनट डेवलपमेंट प्रोग्राम' है, जो कुछ 4000 लाभार्थियों को पौध लगाने की लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देता है। जबकि 20 साल पहले गुजरात भारत के नारियल नक्शे पर कहीं नहीं था। लेकिन नारियल उगाने वाले नारणभाई जैसे शुरुआती किसान अब एक तरह से 'कोकोनट इन्फ्लुएंसर' बन गए हैं। लेकिन अब सभी किसान हाइब्रिड पौधे चाहते हैं, लेकिन राज्य की नर्सरियां साल में सिर्फ 15,000-20,000 पौधे ही तैयार कर पाती हैं, जबकि मांग 5 लाख से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में कुछ किसान जिनमें नारणभाई भी हैं, उन्होंने अपने घरों के पीछे छोटी नर्सरियां बनाकर हाइब्रिड पौधे तैयार करने शुरू किए हैं। नारणभाई ने कहा, 'अभी 300 से ज्यादा किसान पौधे के लिए लाइन में हैं, और इंतज़ार डेढ़ साल से भी ज्यादा है।' हाइब्रिड की इतनी भारी मांग की सबसे बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। धीरे-धीरे, पारंपरिक लोटन किस्म की पैदावार प्रभावित हो रही है। केरल में पिछले एक साल में नारियल उत्पादन 40 प्रतिशत गिर गया है। इस गिरावट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज और वीविल (एक कीड़ा) का हमला, साथ ही दूसरी परेशानियां जैसे रियल एस्टेट के लिए ज़मीन का इस्तेमाल और मजदूरों की कमी है। तमिलनाडु में तो गजा जैसे चक्रवातों ने भी उत्पादन को काफी नुकसान पहुंचाया। गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। नारियल के पेड़ को गर्मी और नमी पसंद है, लेकिन तट पर बढ़ता तापमान नुकसान करने लगा है। किसानो को ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश हर साल अनियमित हो रही है और पैदावार गिर रही है। बावजूद इसके किसान आगे का सपना देख रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत अभी 140 से ज्यादा देशों को नारियल निर्यात करता है। गुजरात के किसान चाहते हैं कि अडाणी और अंबानी गुजरात की नारियल इंडस्ट्री में निवेश करें ताकि राज्यमें निर्यात के अवसर खुल सकें।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित रिपोर्ट के संपादित अंश)

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बोले- पक्ष-विपक्ष मिलकर विकसित

मप्र के साझा संकल्प और भविष्य की दिशा तय करेंगे

- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा आगमन पर की राज्यपाल की अगवानी
- मुख्यमंत्री ने विधानसभा के विशेष सत्र आयोजन पर विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को दी बधाई

जनहित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर हम मध्यप्रदेश की जनता की भलाई के लिए एक नया इतिहास लिखेंगे : श्री तोमर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष सत्र के माध्यम से अतीत की गौरवशाली संसदीय लोकतांत्रिक परंपराओं की स्मृतियां जीवंत हो रही हैं।

इस विशेष सत्र में पक्ष-विपक्ष मिलकर वर्ष 1956 से लेकर अब तक की विधानसभा की यात्रा का पुनरावलोकन करने के साथ-साथ विकसित भारत@2047 और विकसित मध्यप्रदेश के साझा संकल्प और भविष्य की दिशा तय करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशेष सत्र के आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल के विधानसभा आगमन पर उनकी अगवानी की।

हम मध्यप्रदेश की जनता की भलाई के लिए एक नया इतिहास लिख सकेंगे

विशेष सत्र का आयोजन अध्यक्ष म नरेन्द्र सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के अध्यक्ष के नाते मुझे विश्वास है कि इस विशेष सत्र में अपने नेक इरादे, साफ नीयत, जनहित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर विज़न के माध्यम से हम मध्यप्रदेश की जनता की भलाई के लिए एक नया इतिहास लिख सकेंगे। हमारी सहभागिता पहली विधान सभा के संकल्पों के अनुरूप सन् 2047 में मानव विकास के नये प्रतिमानों के साथ विशेष सत्र की धारणाओं को साकार करेगी। हम कह सकेंगे कि मध्यप्रदेश सही अर्थों में भारत का सिरमौर है। विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार, संसदीय कार्यमंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रिगण एवं सदस्यगणों ने प्रदेश के विकास एवं विकसित भारत में प्रदेश की भूमिका के रोडमैप पर अपने विचार रखे।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा के विशेष सत्र के आरंभ में दिवंगतों को किया नमन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा के 17 दिसंबर के विशेष सत्र में निधन संबंधी उल्लेख के अंतर्गत भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज वि. पाटिल, भूतपूर्व राज्यपाल मिजोरम श्री स्वराज कौशल, भूतपूर्व लोकसभा सदस्य डॉ. रामविलास वेदांती और 10 दिसंबर 2025 को नेशनल हाईवे 44 पर बम डिस्पोजल स्क्वॉड के वाहन की कंटेनर से भिड़ंत में मृत आरक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री शिवराज वि.पाटील का स्मरण करते हुए कहा कि लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले श्री पाटिल अनेक संसदीय समितियों के सभापति तथा विभागीय परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। उनके निधन से देश ने एक वरिष्ठ राजनेता, संसदविद् एवं कर्मठ समाजसेवी खो दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री स्वराज कौशल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मिजोरम के एडवोकेट जनरल रहे। वे मिजोरम के राज्यपाल रहने के अतिरिक्त राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए।

राज्यपाल ने विधानसभा की गौरवशाली यात्रा के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने बुधवार को विधानसभा के विशेष सत्र के अवसर पर मध्यप्रदेश विधानसभा के 1956 से 2025 तक के इतिहास के पल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश- विकास और सेवा के दो वर्ष विषय पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने मध्यप्रदेश विधानसभा के 1956 से 2025 तक के इतिहास के पल प्रदर्शनी का फीता खोल कर शुभारंभ किया। उन्होंने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित चित्र प्रदर्शनी के एलबम का भी लोकार्पण किया और प्रदर्शनी के चित्रों का अवलोकन किया। उन्होंने ऐतिहासिक, दुर्लभ चित्र संकलन और प्रस्तुतिकरण की सराहना की। राज्यपाल श्री पटेल ने इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश- विकास और सेवा के दो वर्ष विषय पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल के विधानसभा आगमन पर विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्रीगण, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रथम सत्र के 70 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा के सात दशकों की गौरवशाली यात्रा के दुर्लभ चित्रों की आकर्षक प्रदर्शनी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में लगाई गई है। प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश विधानसभा के 1956 से 2025 तक के इतिहास के 135 दुर्लभ चित्रों का संयोजन किया गया है।

शरद की सुबह

इतना मत इतरा
ओ गुब्बारे!
फूला-फूला उछल-उछल रहा है इधर-उधर
और तुझे पकड़ने को बेताब
यहाँ-वहाँ भाग रहे हैं उचक रहे हैं उछल रहे हैं
मासूम बच्चे
तेरे भीतर नहीं भरी है दिल्ली की प्रदूषित हवा
गुब्बारे वाले के सिलेंडर की
हल्की हवा के बलबूते
इतना उछल रहा है तू होकर
हल्का-पुलका
पर सुन!
ओ गुब्बारे
बेशक़ निकल गया तू.... छूने को आसमान
एक दिन मगर तेरी हवा निकलेगी ज़रूर
तेरी गरदन पर कसी
भरोसेमंद यह कसावट
एक न एक दिन ढीली पड़ेगी
यक़ीनन
फिर तू हुआ पिचका
पड़ा होगा जाने किधर...
इतना मत इतरा
ओ गुब्बारे!

-वसंत सकरगाए

भारतीय कंपनियां इथियोपिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टर

- इथियोपिया की संसद में मोदी बोले-यह शेरों की धरती

अदीस अबाबा (एजेंसी)। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह दुनिया की 18वीं संसद है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया। मोदी ने कहा कि मुझे इथियोपिया आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह शेरों की धरती है। यहां मुझे अपने घर जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा गृहराज्य गुजरात भी शेरों की धरती है। इससे पहले इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने मंगलवार को मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था। वे 'द ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया' पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। मोदी मंगलवार को ही इथियोपिया पहुंचे थे। यह उनका पहला दौरा है। पीएम अबी अहमद अली ने नेशलन पैलेस में उनका औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक भी की। मोदी ने कहा, भारतीय कंपनियां इथियोपिया में सबसे बड़े इंवेस्टर्स में से हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 5 अरब डॉलर (45 हजार करोड़ रुपए) से अधिक का निवेश किया है।

मोदी बोले-

इथियोपिया-भारत के 2000 साल पुराने संबंध- मोदी ने कहा-भारत और इथियोपिया जलवायु और भावना दोनों में एक दूसरे के साथ विचार साझा करते हैं। लगभग 2000 साल पहले, हमारे पूर्वजों ने संबंध स्थापित किए थे। हिंद महासागर के पार व्यापारी मसालों और सोने का व्यापार करते थे, लेकिन वे केवल वस्तुओं का ही व्यापार नहीं करते थे, वे विचारों और जीवन शैली का भी आदान-प्रदान करते थे। अदीस और धोलेरा जैसे बंदरगाह न केवल व्यापार केंद्र थे, बल्कि सभ्यताओं के बीच सेतु भी थे। आधुनिक समय में, हमारा संबंध एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। 1941 में इथियोपिया की मुक्ति के लिए भारतीय सैनिकों ने इथियोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी।

सीएम ममता बनर्जी के भवानीपुर में चली एसआईआर की कैंची

- टीएमसी में खलबली, कार्यकर्ता करेंगे घर-घर जाकर दोबारा चेकिंग

कोलकाता (एजेंसी)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद भाबानीपुर विधानसभा क्षेत्र से 45 हजार वोटरों के नाम हटाए जाने से तृणमूल कांग्रेस में खलबली मची है। भाबानीपुर से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 2011 से लगातार जीत दर्ज करती रही हैं।

अब टीएमसी नेतृत्व ने भाबानीपुर में हटाए गए वोटरों के नाम को घर-घर जाकर दोबारा वेरिफाई करने का अभियान चलाया है। पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंटों को वोटर लिस्ट चेक करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। कोलकाता के चार हाई-प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्रों भाबानीपुर, कोलकाता पोर्ट, बालीगंज और रासबिहारी में कुल मिलाकर 2.16 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए हैं।

राहुल ने म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू प्लांट का किया दौरा

- कांग्रेस नेता ने कहा-भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को जर्मनी के म्यूनिख स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी बीएमडब्ल्यू के मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कारों और मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी ली। वहीं, राहुल गांधी ने इस दौरान भारत की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, भारत में उत्पादन कम हो रहा है, जबकि इसे बढ़ना चाहिए। किसी भी देश की तरक्की के लिए उत्पादन बहुत जरूरी है। हमें ज्यादा उत्पादन करना होगा, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाना होगा और अच्छी नौकरियां पैदा करनी होंगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारतीय विदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल का स्वागत किया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी ने कंपनी की 450वीं मोटरसाइकिल देखी, जो भारत के सहयोग से विकसित की गई है। राहुल ने इसे देखकर गर्व महसूस किया। राहुल 20 दिसंबर तक जर्मनी में ही रहेंगे।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c

न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 18 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

शैक्षणिक भ्रमण-विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं करियर उन्मुख पहल

भोपाल। शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा 17 दिसम्बर को सेज यूनिवर्सिटी, भोपाल का एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण (एजुकेशनल टूर) आयोजित किया गया। यह भ्रमण महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शालिनी सक्सेना के संरक्षण एवं कैरियर सेल प्रभारी डॉ. आशा वर्मा तथा उनकी टीम के कुशल मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली, नवीन शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों एवं रोजगारोन्मुखी अवसरों से अवगत कराना था। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को सेज यूनिवर्सिटी के विशाल एवं सुसज्जित परिसर का अवलोकन कराया गया, जिसमें अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ, डिजिटल एवं भौतिक पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम, अनुसंधान केंद्र तथा नवाचार एवं उद्यमिता से जुड़े विभाग शामिल रहे। यूनिवर्सिटी के विभिन्न संकायों के विशेषज्ञों एवं करियर काउंसलर्स श्री अभिषेक ठाकुर एवं सत्यम नेमा द्वारा विद्यार्थियों को शोध की संभावनाओं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट प्रक्रिया तथा उद्योग-शिक्षा समन्वय की विस्तृत जानकारी दी गई। संवादात्मक सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने करियर से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका समाधान विशेषज्ञों द्वारा सरल एवं प्रेरक ढंग से किया गया।इस अवसर पर विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि किस प्रकार बदलते समय के अनुसार कौशल विकास, तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण उनके भविष्य को सशक्त बना सकता है। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा एवं प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला। इस शैक्षणिक भ्रमण में महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ इला जैन डॉ नीतूप्रिय लाछोरिया डॉ सरला पटेल डॉ दिनेश डहारे डॉ कुल्हार कैरियर सेल के सदस्य एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे विद्यार्थियों ने इस आयोजन को अत्यंत लाभकारी, प्रेरणादायक एवं मार्गदर्शक बताते हुए महाविद्यालय प्रशासन एवं मार्गदर्शक शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

भगोड़े नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने के लिए नई अपील

● 6,498 करोड़ के पीएनबी घोटाले में भारत नहीं आना चाहता

लंदन (एजेंसी)। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने लंदन की एक कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की नई अपील दाखिल की है। भारत की ईडी और सीबीआई की टीमें भी लंदन में मौजूद हैं। वो क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस की मदद कर रही हैं ताकि नीरव की अपील का विरोध किया जा सके।

नीरव को भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और वो पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में ट्रायल का सामना करने के लिए वांटेड है। नीरव पर 6,498 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड का आरोप है। ब्रिटेन की एक कोर्ट ने पहले ही भारत सरकार के पक्ष में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस इंग्लैंड और वेल्स में आपराधिक मामलों की स्वतंत्र रूप से अभियोजन चलाने वाली मुख्य सरकारी एजेंसी है, जो पुलिस और अन्य जांचकर्ताओं द्वारा जुटाए गए सबूतों की समीक्षा करती है, यह तय करती है कि मुकदमा चलाना है या नहीं। नीरव मोदी की तरफ से अब तक जमानत की अर्जियां करीब दस बार खारिज हो चुकी हैं।

विधानसभा के विशेष सत्र में मनरेगा का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले पर विरोध ,प्रदर्शन

मंत्री विजयवर्गीय बोले- सीएम सूट-बूट में आए, हम गरीबों जैसे,कांग्रेस ने कहा- दिल की बात जुबां पर आई

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश विधानसभा ने 17 दिसंबर 2025 को अपने 69 साल के सफर का जश्न मनाने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर 'विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्यप्रदेश' विषय पर एक जीवंत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की भविष्य की दिशा की रूपरेखा पेश की।

एमपी विधानसभा के 69 साल पूरे

मध्यप्रदेश विधानसभा ने 17 दिसंबर 2025 को अपने 69 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष सत्र आयोजित किया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य 'विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्यप्रदेश' की दिशा में चर्चा करना था। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 1956 में गठित विधानसभा की स्मृतियां इस विशेष सत्र से जीवंत हो रही हैं।

इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सूट-बूट पहनकर सदन में आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लेकर कहा, 'मुख्यमंत्री सूट-बूट में आ गए हैं और हम मंत्री-विधायक लोग गरीबों जैसी वेश-भूषा में हैं।' विजयवर्गीय की इस बात पर सदन में ठहाके लगे। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा, दिल की बात जुबां पर आ गई। कहीं न कहीं यह पीड़ा है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्री-विधायकों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज तो विजयवर्गीय ने सदन में यह कह ही दिया।

सत्र की शुरुआत से पहले, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) करने के केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया।

एमपी के अस्पतालों में चूहों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस- डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ल के संबोधन के दौरान अस्पतालों में चूहों का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा और महेश परमार ने कहा कि क्या सरकार यह साफ कर सकती है कि 2026 में अस्पतालों में चूहों से बच्चों की मौत नहीं होगी? इसके बाद अस्पताल में चूहों को लेकर सदन में शोर-शराबे का माहौल बन गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य बहस करने लगे।

निर्मल बाबा द्वारा दी गई समय सीमा भी खत्म हो चुकी है: विस अध्यक्ष तोमर- विजयवर्गीय संबोधन के दौरान जब लंबे समय तक बोलते रहे तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आपके लिए निर्मल बाबा द्वारा दी गई समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। कृपया जल्दी खत्म करें, इस पर सदन में हास परिहास का माहौल बना।

शिवराज सिंह ने एमपी को सबसे ज्यादा योजनाएं दी- विजयवर्गीय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितनी योजनाएं मध्यप्रदेश को दी हैं, उतनी किसी ने नहीं दी और दूसरे राज्य आज भी उनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं।

मंत्री विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तारीफ की- संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी मुख्यमंत्री और उनके कामों के बारे में जानकारी देते हुए सदन को उनकी खूबियों से अवगत कराया।उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और बाबूलाल गौर की जोड़ी प्रसिद्ध थी। पटवारी के कार्यकाल में बाबूलाल गौर ने पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाने का काम जिस तरीके से किया, उसके बाद उन्हें 'बुलडोजर मंत्री' कहा जाने लगा।

सीएम ने बताया वृंदावन गांव बनाने की योजना है- मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दिन पहले ही मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का स्वरूप तय किया गया है। इंदौर और भोपाल को अलार्म में लिया गया है, और 2026 में जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।

सीएम बोले- एमपी में परिवर्तन का नया दौर- मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष सत्र हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल की नगरी से मिली प्रेरणा पूरे राज्य में फैली है। उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर दूरगामी निर्णय लिए हैं, जो आज भले ही छोटे लगें, लेकिन भविष्य में माइलस्टोन बनेंगे और जनता के जीवन में बदलाव लाएंगे, उनके कष्ट कम करेंगे।

मध्यप्रदेश विधानसभा विशेष सत्र 'विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध मप्र'

प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और जेरियाट्रिक केयर-तीनों स्तरों पर समग्र, दूरदर्शी और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ सरकार कर रही है कार्य: उप मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश विधानसभा के 'विकसित आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' विषय पर आयोजित विशेष सत्र में उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और जेरियाट्रिक केयर-तीनों स्तरों पर समग्र, दूरदर्शी और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बीमारी का इलाज करने से बेहतर है बीमारी को होने से रोकना। इसी उद्देश्य से प्रदेश में व्यापक स्तर पर प्रिवेंटिव केयर को सशक्त किया गया है। निरोगी काया अभियान के माध्यम से नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 1.19 करोड़ नागरिकों की हाइपरटेंशन, 1.22 करोड़ की डायबिटीज तथा 1.29 करोड़ लोगों की फैटी लीवर की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए 39.4 लाख लोगों की ओरल कैंसर, 19.3 लाख महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर तथा 8.5 लाख महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की गई है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में मध्यप्रदेश 6 पैरामीटर में देश में शीर्ष पर है। क्यूरेटिव केयर पर प्रकाश डालते हुए उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में टीबी स्क्रीनिंग एवं उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे इस बीमारी का उन्मूलन सुनिश्चित किया जा सके। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग के नागरिकों को गंभीर बीमारियों के लिए निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक लगभग 34 लाख हितग्राही उपचार का लाभ ले चुके हैं तथा योजना के माध्यम से 447 अंग प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में निरंतर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे टर्शरी केयर सुविधाएँ जिला एवं संभाग स्तर तक सुलभ हो सकें। आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की गई है, जिससे बहुमूल्य समय और जीवन दोनों की रक्षा हो सके। जेरियाट्रिक केयर के संबंध में श्री शुक्ल ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत उन्हें निःशुल्क उपचार का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। अब तक लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इ

धामी सरकार 2027 चुनाव से पहले घर-घर देगी दस्तक

● 23 विभागों से जुड़ी योजनाओं से आम लोगों को जोड़ेगी

कांग्रेस बोली-पहले किसके द्वार पर थे, सियासत चरम पर

देहरादून (एजेंसी)। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। उत्तराखंड सरकार 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान में प्रदेश के सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाएगी। इन कैंपों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। लोग ऐसे कैंपों से जुड़े, इसके लिए सोशल मीडिया से भी प्रचार होगा। सभी कैम्प का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। कैम्प का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एक एप भी तैयार होगा। ताकि योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस कार्यक्रम को लेकर तंज कसा है।

हर जिले को बनाना होगा कैंप का रोस्टर

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में न्याय पंचायतों की संख्या के अनुसार कैंप का रोस्टर तैयार करें। जिन जिलों में न्याय पंचायतों की संख्या अधिक है, वहां अभियान तब तक जारी रहेगा,जब तक सभी नागरिक योजनाओं से संतृप्त नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की उपलब्धता को देखते हुए हर सप्ताह 2 से 3 कार्य दिवसों में प्रत्येक तहसील की सभी न्याय पंचायतों को कवर किया जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि कैंप लगाने से पहले संबंधित न्याय पंचायत में सूचना का प्रचार-प्रसार अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग करने को कहा गया है, ताकि लोगों को समय और स्थान की पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि कैंप से 2-3 दिन पहले आवेदन पत्र, योजना की जानकारी और जरूरी दस्तावेजों की सूची गांवों तक पहुंचा दी जाए।

सात भारतीय राज्यों को तोड़ने की धमकी से भारत नाराज

● बांग्लादेश हाई कमिश्नर को किया तलब ,ढाका में वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद

ढाका (एजेंसी)। भारत सरकार ने बुधवार को बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमिदुल्लाह को समन किया है। हाल ही में भारतीय उच्चायोग को एक धमकी मिली थी, जिसके बाद भारत ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि धमकी क्या थी, लेकिन इसे गंभीर सुरक्षा चिंता के रूप में देखा जा रहा है। यह कदम बांग्लादेश के नेशनल सिटिजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्लाह की धमकी के एक दिन बाद उठाया गया। अब्दुल्लाह ने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों (7 सिस्टर्स) को अलग-थलग करने और अलगाववादियों को शरण देने की बात कही थी। अभी किसी कार्रवाई या जवाबी कदम का जिक्र नहीं है। जानकारी के मुताबिक, यह एक औपचारिक कूटनीतिक आपत्ति दर्ज कराने का मामला है। इससे आगे क्या होगा, इस पर फिलहाल कोई विवरण सामने नहीं आया है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर बुधवार दोपहर 2.00 बजे से बंद कर दिया गया है। अब्दुल्लाह ने सोमवार को ढाका में एक रैली में कहा था कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की गई तो बदला लेंगे।

मेजर जनरल श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पेंशनरों को किया सम्मानित

भोपाल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में सैकड़ो पेंशनरों ने पेंशनर दिवस में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल श्याम शंकर श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पेंशनरों का सम्मान कर संबोधन में कहा कि हमारे द्वारा कर्तव्य पूर्ण एवं निष्ठा के साथ की गई सेवा का ही परिणाम है जिसे आज हम विकसित भारत के रूप में देख रहे हैं।

कार्यक्रम में सेवानिवृत्त फौजियों के साथ 60 से अधिक पुरुष एवं महिला पेंशनरों का साल एवं पुष्प माला से स्वागत किया गया। एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने पेंशनर दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का दिन डी एस नकारा बनाम भारत सरकार प्रकरण में 17 दिसंबर 1982 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेंशनर्स के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था की पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव करना असंवैधानिक है, क्योंकि पेंशन कोई कृपा नहीं बल्कि पूर्ण सेवा के लिए एक अधिकार है, जिसका सभी पेंशन भोगियों को समान लाभ मिलना चाहिए।

भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि हमने अपनी आयु का स्वर्णिम समय प्रदेश एवं देश की सेवा में समर्पित किया है, सरकार को हमारे साथ भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है।

कार्यक्रम संचालन प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर ने किया एवं कार्यक्रम को महिला संयोजक रेणू गव्हाड, उपाध्यक्ष शंभू नाथ मुखर्जी, सचिव आर जी माथुर, यशवंत सिंह बेस, अनिल पांडे एवं जिले के संरक्षक पी के सिंघल जिला पदाधिकारी सर्वेश तिवारी, हरेंद्र तिवारी, आर एस यादव, राजेंद्र नायक, मनोज गुप्ता एवं श्रीमती रमा तिवारी ने संबोधित कर सरकार से पेंशनरों की लंबित समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की।

कलाम की जगह वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी बीजेपी

● किताब में दावा-बीजेपी ने अटलजी से कहा था ,आप आडवाणी को पीएम बनने दीजिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के 11वें राष्ट्रपति के लिए भाजपा ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति पद ऑफर किया था। पूर्व पीएम वाजपेयी के करीबी अशोक टंडन ने अपनी किताब 'अटल संस्मरण' में इसका खुलासा किया है। इस किताब के मुताबिक भाजपा ने वाजपेयी से कहा था, पार्टी चाहती है कि आपको राष्ट्रपति भवन चले जाना चाहिए। आप प्रधानमंत्री पद लाल कृष्ण आडवाणी को सौंप दीजिए। हालांकि, वाजपेयी ने इस प्रस्ताव को साफ ठुकरा दिया। टंडन के अनुसार,

वाजपेयी ने कहा था- मैं इस तरह के किसी कदम के पक्ष में नहीं हूं। मैं इस फैसले का समर्थन नहीं करूंगा। टंडन ने 17 दिसंबर, 2025 को वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पर अटल स्मरण किताब लॉन्च की है। यह किताब जीवन, व्यक्तित्व, और राजनीतिक यात्रा पर आधारित है। टंडन 1998 से 2004 तक वाजपेयी के मीडिया सलाहकार थे। वहीं, वाजपेयी 1999 से 2004 तक, 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले देश के पहले गैर-कांग्रेसी पीएम थे। टंडन की किताब में बताया गया है कि वाजपेयी चाहते थे कि देश का 11वां राष्ट्रपति सर्वसम्मति से बने।

● **वाजपेयी-आडवाणी में नीतिगत मतभेद, फिर भी रिश्ते खराब नहीं हुए-** अशोक टंडन ने अपनी किताब में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के संबंधों का भी जिक्र किया है। टंडन ने लिखा-कुछ नीतिगत मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं के रिश्ते कभी सार्वजनिक रूप से खराब नहीं हुए। टंडन के अनुसार, आडवाणी हमेशा वाजपेयी को अपना नेता और प्रेरणा स्रोत बताते थे, जबकि वाजपेयी आडवाणी को अपना अटल साथी बताते थे। किताब के अनुसार, वाजपेयी और आडवाणी की साझेदारी भारतीय राजनीति में सहयोग और संतुलन का प्रतीक रही। दोनों ने न केवल भाजपा का निर्माण किया, बल्कि पार्टी और सरकार, दोनों को नई दिशा दी।

संसद हमले के समय सोनिया ने अटल से फोन पर खैरियत पूछी थी

टंडन ने अपनी किताब में 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया है। उस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वाजपेयी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। हमले के वक्त वाजपेयी अपने आवास पर थे और सहयोगियों के साथ टीवी पर सुरक्षाबलों की कार्रवाई देख रहे थे। टंडन ने किताब में लिखा- हमले के दौरान वाजपेयी को सोनिया गांधी का फोन आया। उन्होंने वाजपेयी से कहा कि मैं आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

एमपी कांग्रेस के 780 ब्लॉक अध्यक्ष घोषित

- जीतू पटवारी के पीसीसी चीफ बनने के ठीक दो साल बाद हुई ब्लॉकों की घोषणा

भोपाल (नप्र)। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के ठीक दो साल बाद मंगलवार 16 दिसंबर को एमपी में कांग्रेस के 780 ब्लॉक अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। भोपाल जिले में बैरसिया के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा बनाए गए हैं। भोपाल उत्तर के यावर जमील, नरेला में फहीम बक्श, भोपाल मध्य में फैज कुरैशी, हुजूर (फंदा) में रामभरोसे राठौर ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं।

11वें अंतरराष्ट्रीय वन मेले की शुरुआत, 350 स्टॉल लगेंगे, किड्स जोन भी रहेगा

- लाल परेड ग्राउंड में चखिये दाल-पानिये का टेस्ट

भोपाल (नप्र)। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में बुधवार से 11वें अंतरराष्ट्रीय वन मेले की शुरुआत हो गयी। इसमें लोग दाल-पानिया, गोंडी जैसी कई डिशेज का लुत्फ भी उठा सकेंगे। 24 राज्य के जड़ी-बूटियों समेत अन्य करीब 350 स्टॉल लगेंगे। किड्स जोन भी यहां रहेगा। इस बार मेला समृद्ध वन खुशहाल वन की थीम पर हो रहा है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। मेले में 350 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मेले में प्रदेश के जिला यूनियन, वन, वन धन केंद्र, जड़ी-बूटी संग्राहक, उत्पादक, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, परंपरागत भोजन सामग्री के निर्माता एवं विक्रेता गण अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करेंगे।

इनके स्टॉल लगेंगे

मेले में 10 शासकीय स्टॉल, 24 अन्य राज्यों के स्टॉल, 16 प्रदर्शनी के स्टॉल, 136 प्राइवेट स्टॉल, 26 फूड स्टॉल, जिनमें अलीराजपुर का दाल पनिया, बांधवगढ़ की गोंडी व्यंजन का स्वाद मिलेगा। इसके अलावा 50 ओपीडी स्टॉल और एक किड्स जोन भी होगा।

200 आयुर्वेद चिकित्सक, विशेषज्ञ देंगे परामर्श- वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया, वन मेले में 200 आयुर्वेदिक पद्धति के चिकित्सक एवं विशेषज्ञ नि:शुल्क चिकित्सीय परामर्श देंगे। प्रबंध संचालक राज्य वनोपज संघ डॉ. समिता राजौरा ने बताया, मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जिसमें ऑर्केस्ट्रा, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए चित्रकला, फैंसी ड्रेस और गायन के कार्यक्रम होंगे।

ये कार्यक्रम होंगे

● 17 दिसंबर की शाम को परंपरागत नृत्य डिंडौरी की प्रस्तुति होगी। ● 18 दिसंबर की शाम ऑर्केस्ट्रा अंचल शर्मा ग्रुप की प्रस्तुति दी जाएगी। ● 19 दिसंबर की शाम विरासत सूफी की म्यूजिकल प्रस्तुति। ● 20 दिसंबर को एक शाम वन विभाग के नाम (फॉरेस्ट मेलोडी) द्वारा सरगम म्यूजिकल ग्रुप। ● 21 दिसंबर की शाम ख्याति प्राप्त सिंगर नीरज श्रीधर, बॉम्बे वाइकिंग्स की म्यूजिकल प्रस्तुति होगी। ● 22 दिसंबर की शाम को मानसरोवर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम।

अजाक्स की तर्ज पर सजाक्स संगठन बनाने की तैयारी

केंद्र-राज्य के पूर्व मंत्री और हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस होंगे संरक्षक, कहा-हर घटनाक्रम पर त्वरित रिएक्शन देंगे

भोपाल (नप्र)। अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) से मैदानी मुकाबले के लिए सामान्य वर्ग के कर्मचारी सनातनी, सामान्य, ओबीसी,अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी एवं पेंशनर्स संघ (सजाक्स) का गठन करने जा रहे हैं। आईएएस और अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद यह निर्णय लिया गया है।

सजाक्स के गठन के लिए मंत्रालय अधिकारी-कर्मचारी सेवा संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक को अधिकृत किया गया है। इस संगठन की सक्रिय शाखाएं ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय तक होंगी। इनके संरक्षक केंद्र व राज्य के पूर्व मंत्री, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस रहेंगे। संगठन एससी-एसटी की तरह सामान्य, ओबीसी वर्ग के मामलों में त्वरित और जमीनी प्रतिक्रिया देगा।

विचार गोष्ठी में हुआ मंथन

आईएएस संतोष वर्मा के मामले में सरकार के लचीले रवैये को देखते हुए पिछले दिनों सामान्य एवं सवर्ण समाज के लोग तुलसीनगर स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुए थे। यहां विचार गोष्ठी हुई, जिसमें वर्मा के विवादित बयान का जिक्र करते हुए कहा गया कि अब ऐसे संगठन की जरूरत है, जो सामान्य और सवर्ण समाज का वजूद स्थापित कर सके। अभी तो ऐसी दुर्दशा है कि देश और प्रदेश में लगातार 20 दिन से प्रदर्शन के बाद वर्मा के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई। जबकि दूसरे मामलों में भोपाल बोलने पर नगालैंड में एफआईआर हो जाती है।

समयमान वेतनमान पर चर्चा- गोष्ठी में सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान लागू नहीं किए जाने पर भी चर्चा हुई। कहा गया कि सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी प्रदेश में 64 प्रतिशत है और एससी-एसटी की 36 प्रतिशत है, फिर भी 36 प्रतिशत हावी है। हाईकोर्ट कई फैसलों में कह चुका है कि सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग की पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है, लेकिन एससी-एसटी को पदोन्नति नहीं दी जा सकती, इसलिए कोई कारण न होते हुए भी एक दशक से सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग को पदोन्नति नहीं दी जा रही है। कोर्ट की अवमानना के केस लगने पर भी इन वर्गों को पदोन्नति नहीं दी गई।

एक दशक में एक लाख से ज्यादा कर्मचारी बिना पदोन्नति रिटायर हो गए, जिसमें अधिकांश सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के थे। जब मांग की गई कि पदोन्नति 2016 से ही शुरू की जाए, तो ये बात नहीं मानी गई। क्योंकि सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी-अधिकारी को फायदा हो सकता था। इसके बाद समयमान वेतनमान के साथ पदनाम ही देने की बात भी नहीं मानी गई, क्योंकि इससे सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी एससी-एसटी की बराबरी पर आ जाते।

गलती होने पर भी साथ दें- गोष्ठी में कहा गया कि जैसे एससी-एसटी वर्ग में होता है, गलत होने पर भी पूरा वर्ग अपने का साथ देता है, वैसा ही हमें भी करना है। वर्मा के तमाम फर्जीवाड़े उजागर होने के बाद भी एससी-एसटी वर्ग उनके समर्थन में खड़ा है।

संगठन की मांगें और उद्देश्य

- 2016 से अब तक रिटायर हुए कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति देकर उनकी पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाए।
- एससी-एसटी वर्ग की 2002 से 2016 के बीच असंवैधानिक ढंग से ली गई पदोन्नतियां समाप्त कराकर उन्हें रिवर्ट कराया जाए।
- एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण लागू किया जाए।
- सनातन धर्म छोड़कर बौद्ध या क्रिश्चियन बन चुके एससी-एसटी को आरक्षण न दिया जाए।
- सनातन धर्म या अन्य किसी भी धर्म के देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, पौराणिक पात्रों, महान पुरुषों, रीति रिवाजों, परंपराओं की निंदा करने, मजाक उड़ाने पर कड़ी कार्रवाई करने का कानून बने।
- शिक्षा और स्वास्थ्य में आरक्षण समाप्त किया जाए और केवल और केवल योग्यता के आधार पर शिक्षक, प्रोफेसर, डाक्टरों की नियुक्ति हो।
- किसी भी स्थिति में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू न हो और आरक्षण को नवमी अनुसूची में शामिल न हो।
- बच्चों को आरक्षण के दुष्प्रभावों से अवगत कराने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाए।

अभी तक 13 लाख 21 हजार मीट्रिक टन से अधिक हुई धान खरीदी

भोपाल (नप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 2 लाख 8 हजार 215 किसानों से 13 लाख 21 हजार 347 मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रूपये प्रति क्विंटल है। धान की खरीदी 20 जनवरी 2026 तक की जायेगी। किसानों को 1122 करोड़ रूपये से अधिक राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि धान विक्रय के लिये 8 लाख 59 हजार 916 किसानों ने पंजीयन कराया है। धान खरीदी के लिये विभिन्न जिलों में 1403 केन्द्र बनाये गये हैं।

तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार टीचर मां-बेटे की मौत

एक अन्य शिक्षक घायल

खरगोन (नप्र)। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़-भुसावल राजमार्ग पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जामली और भोंगानाला के बीच तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक दुपहिया वाहन को आमने-सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला शिक्षिका और उसके शिक्षक पुत्र की मौत हो गई, जबकि एक अन्य शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया।

मौके पर मौत

पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्घटना में 27 वर्षीय ऋतुराज बिलवे की मौके पर ही मौत हो गई। ऋतुराज के साथ उसकी मां 50 वर्षीय मधुबाई और एक अन्य शिक्षक प्रदीप अकोले दुपहिया वाहन पर सवार थे। टक्कर के बाद मधुबाई और प्रदीप को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान मधुबाई ने भी दम तोड़ दिया। घायल प्रदीप अकोले का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।

बाइक का पहिया उखड़ा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि दुपहिया वाहन का अगला पहिया उखड़कर अलग हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल प्रदीप अकोले ने बताया कि पिकअप वाहन गलत साइड से तेज गति में आ रहा था और उसका चालक नशे की हालत में प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने मौके से पिकअप वाहन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक ऋतुराज बिलवे संविदा शिक्षक था, जबकि उसकी मां मधुबाई शासकीय शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। घायल प्रदीप अकोले भी संविदा शिक्षक है। प्रदीप के भाई ने बताया कि ब्रज विहार कॉलोनी, खरगोन निवासी ऋतुराज, उसकी मां और प्रदीप प्रतिदिन रायसागर स्थित स्कूलों में पढ़ाने के लिए आते-जाते थे। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है।

उज्जैन में लैंड पूलिंग पूरी तरह से रद्द

मोहन सरकार के फैसले से किसान संगठनों में खुशी, कहा- अभी कानूनी पहलू को देखेंगे

उज्जैन (नप्र)। लैंड पूलिंग को लेकर किसानों का प्रदर्शन उज्जैन में जारी था। किसानों के विरोध को देखते हुए सरकार ने पिछले दिनों लैंड पूलिंग रद्द करने का आदेश दिया था। अब लैंड पूलिंग को सरकार ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। सिंहस्थ 2028 को लेकर एमपी सरकार खुद ही इस पक्ष में थी। इसके विरोध में किसान, भारतीय किसान संघ, कांग्रेस विधायक महेश परमार, भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय और अनिल जैन थे।

किसान के संघ के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग- वहीं, इस योजना को लेकर भारतीय किसान संघ के दबाव के कारण खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री और किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करना पड़ी थी। इसके कारण यह मामला काफी चर्चाओं में आ गया। बीते 17 नवंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी की सकारात्मक चर्चा हुई थी और लैंड पूलिंग वापस लेने का आश्वासन दिया था।

पहले जारी हुआ था संशोधित पत्र- वहीं, दो दिन बाद 19 नवंबर को सरकार द्वारा जारी आदेश में लैंड पूलिंग वापस लेने की बजाए संशोधित करने का पत्र जारी किया गया। भारतीय किसान संघ ने विरोध कर दिया और आगामी 26 दिसंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई की घोषणा कर दी। हालांकि अब योजना पूरी तरह निरस्त होने के कारण आगामी 26 दिसंबर को भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी दिनेश कुलकर्णी उज्जैन आएंगे। योजना निरस्त का जश्न मनाया जाएगा।

कानूनी पहलुओं पर चिंतन कर रहे

सिंहस्थ लैंड पूलिंग निरस्त को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री भारत सिंह बैस का कहना है कि हमें पत्र प्राप्त हो गया है। हम इसके कानूनी पहलुओं पर चिंतन कर रहे हैं। हालांकि यह योजना निरस्त हो गई, इसकी हमें खुशी है। गौरतलब है कि फरवरी माह में इस योजना का विरोध शुरू हो गया था। सबसे पहले किसानों ने ही विरोध का बिगुल बजाया था। उसके बाद कांग्रेस विधायक महेश परमार किसानों के साथ पहुंचे और प्रभात फेरिया निकाली थी । वहीं, भाजपा के विधायक चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा में इस योजना को किसानों के खिलाफ बताया और योजना निरस्त की मांग की थी। फिर भारतीय किसान संघ ने किसानों का साथ दिया और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तक यह मामला पहुंचा। भारतीय किसान संघ द्वारा करीब चार बार बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए। दो दिन पहले भाजपा विधायक अनिल जैन ने भारतीय किसान संघ का खुलकर समर्थन किया और योजना निरस्त की मांग कर डाली।

हथियारों की बंद फैक्ट्री पर पुलिस का छापा

कमरे में मिले 75 चाकू और 4 तलवारें, दो सगे भाई बनाकर बेचते भी थे

भोपाल (नप्र)। भोपाल की कमला नगर पुलिस ने एक कमरे में चल रही अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा है। जहां से 75 छुरी और 4 तलवारों को जब्त किया है। यहीं से पुलिस ने दो भाई सगे भाईयों को गिरफ्तार किया है।

दोनों भाई ने घर के एक कमरे में कारखाना बना रखा था। यहां से बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण करने के बाद बेचने का काम किया जाता था। लंबे समय से पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई के प्रयास कर रही थी। जिसकी भनक लगते ही आरोपियों ने कारखाने में ताला लगा दिया था।

दबिश देकर कमरा चेक किया, मिले हथियार

टीआई निरूपा पांडे ने बताया कि दुर्गेश विश्वकर्मा और चंदन विश्वकर्मा बापू नगर में रहते हैं। दोनों छुरी-चाकू बनाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले पुलिस की सख्ती के चलते दोनों आरोपियों ने काम बंद कर दिया था।

आरोपी चंदन का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। मुखबिर की सूचना पर आरोपियों के ठिकाने पर मंगलवार की देर रात दबिश दी।

जहां एक बंद कमरे को खुलवाकर चेक किया तो बड़ी संख्या में हथियार मिले। आरोपियों ने बताया कि हथियारों को बेचने के लिए तैयार किया था। पुलिस की सख्ती के चलते बाहर नहीं ले जा सके। लिहाजा तैयार हथियारों कारखाने वाले कमरे में ही बंद रखा।

हर साइज के हथियार तैयार करते थे आरोपी- बुधवार को पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ऑर्डर पर हथियार खपाने का काम करते थे। हर साइज में उनके द्वारा हथियारों को तैयार किया जाता था। तलवारों को अलग-अलग डिजाइन में तैयार करते थे।

एक साल पहले भी हुई थी कार्रवाई

पुलिस ने हथियारों की तस्करी के आरोप में दुर्गेश विश्वकर्मा और चंदन विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया था। तब भी इनके ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार मिले थे। इसके बाद से ही आरोपियों का काम बंद था।

पिछले कुछ समय से लगातार पुलिस को आरोपियों द्वारा दोबारा कारखाने में अवैध हथियार बनाने की जानकारी मिल रही थी। तब पुलिस ने चार टीमें आरोपियों की निगरानी में लगा रखी थीं। पुख्ता सूचना मिलते ही घर में बने कारखाने में दबिश देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई।

एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का मामला

189 यूनिट खून चढ़ा, 200 डोनर जांच के दायरे में

भोपाल/सतना (नप्र)। सतना जिला अस्पताल से सामने आया थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का मामला सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर

रहा है। नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर 4 बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश पर राज्य स्तरीय 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जिसे 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी।

70 से 100 बार चढ़ चुका था खून, खतरा बढ़ा

सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. देवेंद्र पटेल के अनुसार, इन बच्चों को अब तक 70 से 100 बार तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा चुका है। ऐसे मामलों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चों को सिर्फ सतना जिला अस्पताल ही नहीं, बल्कि रीवा के बिरला अस्पताल सहित अन्य जिलों से भी ब्लड सप्लाई की गई थी। तफ्तीश में यह बात उजागर हुई है कि चारों बच्चे करीब 200 ब्लड डोनर के संपर्क में आए और 3 अलग-अलग ब्लड बैंकों के जरिए अब तक 189 यूनिट ब्लड चढ़ाया जा चुका है। अब सभी संभावित डोनरों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है।

जांच में सामने आया है कि ये चारों बच्चे पहले आईसीटीसी जांच में एचआईवी नेगेटिव थे, लेकिन बाद की जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

संपादकीय

अब 'रामजी' के भरोसे मनरेगा

मोदी सरकार और भाजपा को मनरेगा से राजनीतिक परेशानी तो पहले भी थी, लेकिन अब इस योजना के नाम में से भी महात्मा गांधी शब्द हटाया जा रहा है। सरकार वर्तमान मनरेगा कानून की जगह नया कानून लेकर आ रही है। इसे नया रोजगार विधेयक कहा जा रहा है। इस नए विधेयक का पूरा नाम 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (संक्षेप में VB-G RAM G) बिल, 2025 है। यानी नये विधेयक में महात्मा गांधी का नाम गायब है। विधेयक का उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना बताया गया है। बताया जाता है कि यह विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। लेकिन इस पर अभी से विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि योजना से 'गांधी' नाम हटा कर राम के नाम पर गरीबो को दंडित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नया विधेयक ग्रामीण परिवारों को अकुशल मैनुअल कार्य के लिए प्रति वर्ष 100 दिनों की बजाय 125 दिन रोजगार देगा। लेकिन हकीकत में इसका उल्टा होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि सरकार ने नई योजना की फुल फंडिंग से हाथ खींचते हुए इसमें केन्द्र और राज्य सरकार का योगदान 60:40 कर दिया है। राज्य सरकारों के पास वैसे भी पैसा नहीं है और रेवड़ी कल्चर में उनका बहुत सारा पैसा जा रहा है। अगर राज्य इसके लिए पैसा नहीं दे सके तो केन्द्र का हिस्सा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर योजना में पलीता लग जाएगा। इसमें फंडिंग का बोझ राज्यों पर बढ़ जाएगा। सरकार ने सोमवार को लोकसभा सदस्यों के बीच इस विधेयक की प्रति दी है। योजना के तहत सार्वजनिक कार्य जैसे कि - जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और चरम मौसम घटनाओं से निपटना आदि काम कराए जाएंगे। वैसे मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी काफी मिली हैं, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग की प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। नए कानून में योजना की सख्त मॉनिटरिंग का प्रावधान किया गया है। लेकिन इससे कागजी कार्रवाई भी बढ़ेगी। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास जॉन ब्रिटास ने कहा कि यह मनरेगा की मूल संरचना को तोड़ रहा है, केंद्र की भूमिका बढ़ा रहा है और राज्यों पर अव्यावहारिक बोझ डाल रहा है। महात्मा गांधी का नाम हटाना तो सिर्फ़ ट्रेलर है, असली नुकसान कहीं ज़्यादा गहरा है। सरकार ने अधिकार-आधारित गारंटी कानून की आत्मा को खत्म कर दिया और उसकी जगह एक शर्तिया, केंद्र द्वारा नियंत्रित योजना ले आई है, जो राज्यों और मज़दूरों के खिलाफ है। मनरेगा योजना को तत्कालीन यूपीए 1 सरकार ने 2005 में लागू किया था और 2009 में इसके नाम में महात्मा गांधी जोड़ा गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है, जो ग्रामीण गरीबी कम करने, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण रही है। हालांकि, सरकार का तर्क है कि ग्रामीण भारत बदल गया है, गरीबी घटी है, डिजिटल पहुंच बढ़ी है, इसलिए नई, आधुनिक योजना की जरूरत है। बहरहाल, मोदी सरकार द्वारा यह विधेयक संसद में पेश किए जाने पर जोरदार बहस का विषय बनेगा। क्योंकि विपक्ष इसे मनरेगा को खत्म करना बता रहा है, जबकि सरकार इसे आधुनिक, इंफ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित और डिजिटल रूप में सुधार बता रही है। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होगा, इसलिए विधेयक पर चर्चा और मतदान जल्द हो सकता है। ग्रामीण आजीविका से जुड़ा यह बदलाव राजनीतिक रूप से संवेदनशील साबित हो सकता है। किसी भी योजना में बदलाव का हर सरकार को है, लेकिन इससे यह संदेश भी जाना चाहिए कि यह वास्तव में लोगों के हित में है। और महात्मा गांधी का नाम हटाना किसी के गले नहीं उतर रहा।

वंदेमातरम् में राष्ट्र की चेतना की झलक

नजरिया

अरविंद जयतिलक
वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार, लेखक एवं टीवी डिबेटर हैं।

गीत के इतिहास में जाएं तो 7 नवंबर 1875 को बंगाल के कांठलपाड़ा गांव में बंकिमचंद्र चटर्जी ने इस गीत के पहले दो छंदों की रचना की थी। 1937 में कांग्रेस ने ये ही दो छंद अपनाए थे। रचना के सात साल बाद 1882 में उपन्यास 'आनंदमठ' में इसे पूरा करके सम्मिलित किया गया था। 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' के 1896 के अधिवेशन में कलकत्ता में पहली बार ये गीत गूंजा। महान कवि रबीन्द्रनाथ टैगोर ने इसे सुर और ताल दिए और पहली बार राजनीतिक मंच पर गाया। ब्रिटिशों ने इसे बैन करने की कोशिश भी की। सुभाष चंद्र बोस ने इसे 'आजाद हिन्द फौज' का मार्चिंग सॉन्ग बनाया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1915 से हर कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया। अरबिंदो घोष ने अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में इसका अनुवाद किया। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 'राष्ट्रगान' 'जनगणमन' के साथ 'राष्ट्रगीत' 'वंदे मातरम्' की घोषणा की। मूल रुप से 'वंदेमातरम्' के प्रारंभिक दो पद संस्कृत में थे और शेष गीत बांग्ला में।

भारत 'वंदेमातरम्' गीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। चारों ओर 'वंदेमातरम्' की गूंज से भारतीयता का भाव गुंजायमान है, लेकिन विडंबना है कि यह कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। वे कुतर्कों का सहारा लेकर किस्म-किस्म से विरोध की प्रस्तावना खींच रहे हैं। यह ठीक नहीं है। उन्हें समझना होगा कि 'वंदेमातरम्' किसी धर्म या मजहब के समर्थन या विरोध में नहीं है। यह मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और बलिदान का वह निश्छल भाव है जिसे विचारों का हथियार बनाकर आजादी के दीवानों ने मातृभूमि को आजाद कराया। राष्ट्रगीत 'वंदेमातरम्' केवल शब्द भर नहीं हैं, बल्कि इसमें राष्ट्र की संस्कृति, इतिहास, कला, साहित्य और ज्ञान-विज्ञान का वह भाव समाहित है जो भारत राष्ट्र की निरंतरता और चेतना को उद्घाटित करता है। इसके प्रकटीकरण से राष्ट्र की गरिमा और गौरव में वृद्धि होती है।

गीत के इतिहास में जाएं तो 7 नवंबर 1875 को बंगाल के कांठलपाड़ा गांव में बंकिमचंद्र चटर्जी ने इस गीत के पहले दो छंदों की रचना की थी। 1937 में कांग्रेस ने ये ही दो छंद अपनाए थे। रचना के सात साल बाद 1882 में उपन्यास 'आनंदमठ' में इसे पूरा करके सम्मिलित किया गया था। 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' के 1896 के अधिवेशन में कलकत्ता में पहली बार ये गीत गूंजा। महान कवि रबीन्द्रनाथ टैगोर ने इसे सुर और ताल दिए और पहली बार राजनीतिक मंच पर गाया। ब्रिटिशों ने इसे बैन करने की कोशिश भी की। सुभाष चंद्र बोस ने इसे 'आजाद हिन्द फौज' का मार्चिंग सॉन्ग बनाया। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1915 से हर कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया।

अरबिंदो घोष ने अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में इसका अनुवाद किया। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 'राष्ट्रगान' 'जनगणमन' के साथ 'राष्ट्रगीत' 'वंदे मातरम' की घोषणा की। मूल रुप से 'वंदेमातरम्' के प्रारंभिक दो पद संस्कृत में थे और शेष गीत बांग्ला में। दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गीत को 'राष्ट्रगीत' का दर्जा प्रदान किया गया और बंगाल विभाजन के समय यह गीत राष्ट्रीय नारा बन गया। 1906 में 'वंदेमातरम' देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया गया।

सन् 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इस्लाम की भावना के विरुद्ध बताकर 'वंदेमातरम्' गीत का विरोध किया गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरु, सुभाषचंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और आचार्य नरेंद्र देव की समिति ने 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पेश अपनी रिपोर्ट में इस गीत के पहले दो पैराग्राफ को राष्ट्रगीत के रुप में स्वीकृति दे दी। 14 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि में 'संविधान सभा' की पहली बैठक का प्रारंभ 'वंदेमातरम' के साथ और समापन राष्ट्रगान 'जनगणमन' के साथ हुआ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1905 में वंदेमातरम् गीत के संबंध में लिखा है कि - 'आज लाखों लोग एक बात के लिए एकत्र होकर वंदेमातरम गाते हैं, मेरे विचार से इसने हमारे राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल कर लिया है। मुझे यह पवित्र, भक्तिपरक और भावनात्मक गीत लगता है। कई अन्य राष्ट्रगीतों के विपरित यह किसी अन्य राष्ट्र-राज्य की नकारात्मकताओं के बारे में शोर-शराबा नहीं करता है।' 1936 में भी गांधी जी ने 'वंदेमातरम्' के बारे में कहा कि - 'कवि ने हमारी मातृभूमि के लिए जो अनेक सार्थक विशेषण प्रयुक्त किए हैं, वे एकदम अनुकूल हैं, इनका कोई सानी नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन विशेषणों को यथार्थ में बदलें। मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि यह गीत सिर्फ हिंदुओं के लिए रचा गया है।'

आजादी के आंदोलन के अलावा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जब 'अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस' का अधिवेशन शुरु हुआ तो श्यामजी वर्मा, मैडम कामा, विनायक सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता पर संकल्प पारित करने के लिए भाषण से पहले आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रीय झंडे को फहराया और इस झंडे के मध्य में देवनागरी लिपि में 'वंदेमातरम' लिखा। यहां ध्यान देना होगा कि 1906 से 1911 तक यह गीत पूरा गाया जाता था। इस गीत में वह ताकत थी कि ब्रिटिश हुकूमत को बंगाल के विभाजन का फरमान वापस लेना पड़ा। भगत सिंह, मदनलाल ढींगरा, राजगुरु, अशफाकउल्ला और रामप्रसाद 'बिस्मिल' जैसे क्रांतिकारियों ने 'वंदेमातरम' के नारे के साथ फांसी के फंदे को चूमा था।

'वंदेमातरम' गीत राष्ट्रीयता का स्वर है, साथ ही क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी। यह ठीक नहीं है कि कुछ सियासी दल और संगठन अपने राजनीतिक फायदे के लिए 'वंदेमातरम्' को राजनीतिक संकीर्णता के दायरे में रखकर इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। भला इस गीत से किसी मजहब और संप्रदाय को किस तरह चोट पहुंच सकती है?

वंदेमातरम् का विरोध कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। गत वर्ष सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने वंदेमातरम् के गायन को इस्लाम की भावना के खिलाफ बताया था। 2013 में, जब वे बीएसपी सांसद थे, 'वंदेमातरम्' का अपमान कर इसकी धुन बजने पर सदन से उठकर चले गए थे। उनके इस शर्मनाक कृत्य की तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने निंदा करके जवाबतलबी भी की थी। गत वर्ष पहले मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी वंदेमातरम् के गायन पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन जब देश भर में इस निर्णय की आलोचना हुई तब यू-टर्न लेते हुए फैसला लिया गया कि हर महीने के पहले कार्य दिवस पर पुलिस बैंड की धुनों पर 'वंदेमातरम्' गाया जाएगा।

गत वर्ष जब मद्रास उच्च न्यायालय ने 'वंदेमातरम्' को तमिलनाडु के स्कूलों में सप्ताह में कम-से-कम दो बार गायन अनिवार्य किया, तब भी कुछ सियासी दलों ने हायतौबा मचाना शुरु किया था। इसे मजहबी फ्रेम में फिटकर इस्लाम की भावना के विरुद्ध सियासी शोर में बदलने की कोशिश की गई। आज भी कुछऐसा ही उपक्रम देखने को मिल रहा है। कुछ सियासी दल और राष्ट्र विरोधी संगठन 'वंदेमातरम' पर अनावश्यक वितंडा खड़ाकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। देश के जनमानस को ऐसे प्रपंचियों और अराजकवादियों से सतर्क और सावधान रहना होगा।

डिजिटल माध्यमों पर प्रतिबंध

डॉ. प्रियंका सौरभ
लेखक शोधार्थी हैं।

बाल-सुरक्षा और तकनीकी समाधानवाद

डिजिटल युग में बच्चों और किशोरों का जीवन केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं रह गया है। सामाजिक माध्यम, ऑनलाइन मंच और आभासी समुदाय आज उनके सीखने, अभिव्यक्ति, पहचान और सामाजिक संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इन मंचों पर बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सामाजिक माध्यमों पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव इसी चिंता से उत्पन्न हुआ है। परंतु इस कदम को लेकर यह आलोचना भी सामने आई है कि यह एक जटिल मनो-सामाजिक समस्या का अत्यधिक सरलीकृत, तकनीक-आधारित समाधान है, जिसे 'तकनीकी समाधानवाद' कहा जा रहा है।

तकनीकी समाधानवाद का अर्थ है यह मान लेना कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केवल तकनीकी नियमों, प्रतिबंधों या उपकरणों के माध्यम से हल किया जा सकता है। बच्चों के संदर्भ में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से सीमित प्रतीत होता है, क्योंकि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, सामाजिक तुलना, ऑनलाइन उत्पीड़न, अकेलापन और व्यवहारिक परिवर्तन केवल मंच तक पहुँच रोक देने से समाप्त नहीं होते। ये समस्याएँ परिवार, विद्यालय, सहपाठी समूह, सामाजिक वातावरण और व्यापक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से गहराई से जुड़ी होती हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रस्ताव इन जटिल कारणों की बजाय सीधे निषेध पर केंद्रित दिखाई देता है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित कानून के अनुसार, सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सामाजिक माध्यमों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा और आयु-सत्यापन की अनिवार्य व्यवस्था लागू की जाएगी। पहली दृष्टि में यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए कठोर और निर्णायक लगता है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर इसके कई प्रश्नचिह्न हैं। आयु-सत्यापन के लिए व्यापक व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करनी पड़ सकती है, जिससे बच्चों और उनके अभिभावकों की निजता पर खतरा उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी उपायों को आभासी निजी नेटवर्क, फर्जी पहचान या नए, कम नियंत्रित मंचों के माध्यम से आसानी से दरकिनार किया जा सकता है। इससे न केवल कानून की प्रभावशीलता कम होती है, बल्कि बच्चे अधिक जोखिमपूर्ण डिजिटल स्थानों की ओर भी जा सकते हैं।

पूर्ण प्रतिबंध का एक और गंभीर पक्ष यह है कि यह बच्चों को सामाजिक माध्यमों से मिलने वाले सकारात्मक अवसरों से भी वंचित कर सकता है। आज अनेक बच्चे इन्हीं मंचों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री प्राप्त करते हैं, रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं, सामाजिक मुद्दों पर जागरूक होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता समूहों से जुड़ते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण, पिछड़े या सामाजिक रूप से हाशिये पर खड़े बच्चों के लिए डिजिटल मंच कई बार अभिव्यक्ति और सहयोग का एकमात्र साधन होते हैं। ऐसे में पूर्ण प्रतिबंध सामाजिक असमानताओं को और गहरा कर सकता है। यह दृष्टिकोण यह भी संकेत देता है कि समस्या का मूल बच्चों या तकनीक में है, जबकि वास्तव में समस्या उस सामाजिक ढाँचे में है जिसमें बच्चों का डिजिटल समाजीकरण हो रहा है।

भारत ने इसी संदर्भ में एक भिन्न और अपेक्षाकृत संतुलित मार्ग अपनाया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष निषेध के बजाय अधिकार-आधारित और डेटा-केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह अधिनियम यह स्वीकार करता है कि बच्चों को डिजिटल संसार से अलग-थलग करना न तो संभव है और न ही वांछनीय। इसके स्थान पर, यह आवश्यक है कि डिजिटल मंचों को उत्तरदायी बनाया जाए और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इस कानून के अंतर्गत बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सत्यापित अभिभावकीय सहमति को अनिवार्य किया गया है, जिससे परिवार की भूमिका सुदृढ़ होती है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बच्चों के व्यवहारिक निगरानी, व्यक्तित्व-आधारित वर्गीकरण और लक्षित विज्ञापनों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाता है। इससे बच्चों को उपभोक्ता के रूप में शोषण से बचाने का प्रयास किया गया है। साथ ही, यह अधिनियम बच्चों को डेटा तक पहुँच, उसमें सुधार, उसे हटाने और शिकायत दर्ज कराने जैसे अधिकार प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण बच्चों को केवल संरक्षण की वस्तु न मानकर उन्हें अधिकार-संपन्न नागरिक के रूप में देखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अतिरिक्त, भारत में एक स्वतंत्र डेटा संरक्षण बोर्ड की व्यवस्था की गई है, जो नियमों के उल्लंघन पर दंड निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार, मंचों और डेटा का प्रसंस्करण करने वाली संस्थाओं पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, बिना यह कहे कि बच्चों को डिजिटल मंचों से बाहर कर दिया जाए। यह मॉडल यह भी दर्शाता है कि कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, डिजिटल साक्षरता, विद्यालयों में ऑनलाइन सुरक्षा शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार अनिवार्य है। केवल कानून बनाकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, बल्कि एक समग्र सामाजिक प्रयास की आवश्यकता होती है।

ऑस्ट्रेलिया और भारत के दृष्टिकोणों की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर नियंत्रण और निषेध पर आधारित नीति है, वहीं दूसरी ओर संतुलन, सहभागिता और सशक्तिकरण पर आधारित ढाँचा। ऑस्ट्रेलिया का प्रस्ताव त्वरित समाधान का आभास देता है, किंतु दीर्घकाल में यह व्यवहारिक, संवैधानिक और सामाजिक चुनौतियों से घिर सकता है। इसके विपरीत, भारत का मॉडल धीमा और जटिल अवश्य है, परंतु यह बच्चों की स्वायत्तता, निजता और विकास के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करता है।

अंततः, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का प्रश्न केवल यह नहीं है कि उन्हें किससे दूर रखा जाए, बल्कि यह भी है कि उन्हें किस प्रकार सशक्त बनाया जाए। डिजिटल युग में बाल-सुरक्षा का अर्थ बच्चों को तकनीक से अलग करना नहीं, बल्कि उन्हें तकनीक के साथ सुरक्षित, जागरूक और जिम्मेदार बनाना है। सरल तकनीकी समाधान जटिल मानवीय समस्याओं का स्थान नहीं ले सकते। इस संदर्भ में भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढाँचा यह संकेत देता है कि संतुलित नियमन, अभिभावकीय सहभागिता, मंचों की जवाबदेही और सामाजिक समर्थन के माध्यम से ही बच्चों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भविष्य का निर्माण संभव है।

प्रदेश में 6 साल में 2916 बाल विवाह

मुद्दा

संदीप कुलश्रेष्ठ

मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत एक जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से 2025 के बीच 6 साल प्रदेश में कुल 2916 बाल विवाह हुए हैं। ये वह मामले हैं जो पंजीकृत हुए है। जो पंजीकृत हुए उससे ज्यादा ऐसे बाल विवाह हैं, जो पंजीकृत ही नहीं हुए है। उसे मिलाकर संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है। हर साल बाल विवाह के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है। यह किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। महिला सशक्तिकरण के लिए बाल विवाह रोकना बहुत जरूरी है।

वर्षवार हुए बाल विवाह

विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में जहाँ 366 बाल विवाह हुए थे, वहीं इस वर्ष 2025 में अभी तक 538 बाल विवाह हो चुके हैं। वर्ष 2021 में 436, वर्ष 2022 में 519, वर्ष 2023 में 528, वर्ष 2024 में 529 बाल विवाह हुए हैं। वर्षवार बाल विवाह की बढ़ती संख्या चिंताजनक है।

सर्वाधिक बाल विवाह वाले जिले

प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं, जहाँ सर्वाधिक बाल विवाह हो रहे हैं। पिछले 6 साल में दमोह में 343, राजगढ़ में 215, सागर में 202, गुना में 146 और देवास में 121 बाल विवाह हुए है। यह बहुत गंभीर बात है। इस पर तुरंत नियंत्रण की आवश्यकता है।

1200 से ज्यादा नाबालिग माँ बनीं

मध्यप्रदेश में पिछले 6 साल में 1200 से ज्यादा नाबालिग माँ बनी। यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के जन्म-पंजीयन एवं महिला एवं बाल विकास की रिपोर्ट से सामने आया। देश में औसत नवजात मृत्युदर (0-28 दिन में मौत) 27 हैं। अर्थात् एक हजार बच्चों के जन्म पर 27 बच्चों की मौत हो जाती है, जबकि मध्यप्रदेश में यह दर 36 है। नाबालिग माताओं से जन्में बच्चों में यह मौत दर सामान्य से दोगुनी है।

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020-22 की रिपोर्ट

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में 40 प्रतिशत नवजात कुपोषित पैदा होते हैं। उनमें से 20 प्रतिशत बच्चे एक साल भी नहीं जी पाते। नाबालिग से जन्में बच्चों में पहले 30 दिनों में मौत का खतरा सबसे ज्यादा है। राजगढ़ जिले में 2025 के पहले 8 महीनों में ही 52 नाबालिग माताओं ने 53 कुपोषित बच्चों को जन्म दिया। इनमें से 10 बच्चों की 30 दिन के अंदर ही मौत हो गई।

जनजागरण चलाने की है जरूरत

प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार अनेक योजनाएं चलाती है। इसके बावजूद पिछले 6 साल में 46.99 प्रतिशत बाल विवाह बढ़ गए। यह अत्यधिक चिंता की बात है। इसके लिए केवल शासन पर जिम्मेदार नहीं डाली जा सकती। बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवार और नाते-रिश्तेदारों में यदि बाल विवाह होने जा रहे हों तो उसे रोकने में तुरंत मदद करें। यदि समझाइश के बाद भी नाबालिग बच्चियों के माता-पिता शादी करने के लिए डटे रहे तो पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग की मदद लेकर बाल विवाह रोके जाने चाहिए। बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बाल विवाह होने से बच्चियाँ पढ़ाई से दूर हो जाती है। और उसका शारीरिक और मानसिक विकास भलीं-भाँती नहीं हो पाता है। इसलिए हर एक माता-पिता की जिम्मेदारी है कि वे बाल विवाह पर रोक लगाए तभी बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. प्रेमचंद द्वितीय
लेखक व्यंग्यकार हैं।

मुएं ये कागज शेर से कम नहीं

राजस्थान के झालावाड़ में, गांव के गांव कागजी दिव्यांग, बन गए खबर पढ़कर पंडित शिवनारायण जी सुबह-सुबह घर धमके और बोले मुएं ये कागज भी अनोखे हैं। चलते-फिरते, भागते दौड़ते, हष्ट पुष्ट, बलशाली, भले चंगे, सभी अंगों से बलशाली होने वाले को भी कागज दिव्यांग बनाकर पेंशन एठने के अस्त्र बन जाते हैं । वैसे भी कागज की महिमा अपरंपार है। पूरी दुनिया के लेखे जोखे , व्यापार व्यवसाय कार्यालय, पढ़ाई लिखाई ,यहां तक की प्रेम के रास्ते भी कागज पर लिखे प्रेम पत्रों से गुजरते हैं । कागज विकास की आधारशिला है तो यही कागज विनाश के साइलेंट शस्त्र भी है इसी कारण कागज का टुकड़ा मात्र पुर्जा नहीं वरन अच्छे कामों का आधार स्तंभ है और बुरे कामों की हकीकत खोलने वाले होते हैं ।

वे बोले कागज की महिमा को कोई पार नहीं कर सकता। सौ बका और कागज पर एक लिखा सौ के बराबर होता है। जब चलते-फिरते हैं कागजी दिव्यांग बनते हो होंगे तो कानों से अच्छा सुनने वालों को बहरा और चकाचौंध देखने वालों को अंधेरा देखना बताना पड़ता होगा। चलने दौड़ने वालों को बैसाखी संभालना पड़ती है तभी कागजी दिव्यांग बन पाते होंगे। इस पर घर पर साधु राम जी आए और बोले फर्जी दिव्यांग कागज ही बना सकते हैं। कागज पर क्या नहीं बनता, कागज पर सड़क, तालाब, नल ,टंकी , योजना, भवन सब बनते हैं । अनेक कार्यकाल में तो समस्याओं का अंबार कागज समेटे हुए रखते हैं । करोड़ों के कामकाज कागज की तिजोरी में कब लुप्त हो जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। वे बोले कागज दुबला पतला साफ सुथरा स्वरुप वाला होता है, जब कागज शिकायती बनते हैं तो अच्छे-अच्छे को पसीना ला देते हैं ।कई तो कागज पर शिकायत कर कर कागजी शेर बन गए और शेरों को बकरी की तरह मिमियाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे बोले कॉलोनी के छेदीलाल जी ने कागजों पर शिकायत लिख लिख कर अपना जीवन निकल लिया। वे किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते तो कागज से वार कर उनको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कोई कमजोर ,वांछित होता है तो उसे आगे बढ़ाकर कागज को चलाकर उसे अपना हमसफर, हमसफर, हमराह बनाने की कोशिश करते हैं। वे बोले कागजी घोड़े तो टेबल पर इधर से दौड़-दौड़ कर थक गए हैं और लाल फीतों के अस्तबल में चले गए हैं । उनका न ही कोई वैभव, न ही कोई प्रभाव रहा है । अब तो सोशल मीडिया पर कागजों की प्रतिलिपि फॉरवर्ड होती है जिससे अनेक बैकवर्ड हो जाते हैं ।

इस पर कागज चलाने में माहिर लचक राम जी बोले कागजी नींबू असली नींबू के विटामिन सी से ज्यादा कागजी बादाम, कागजी ड्राय फ्रूट जब दिए जाते हैं तो उनसे मिले विटामिन रिकमेंड, विटामिन रिश्वत, विटामिन घूंस, विटामिन पेशगी इन्हीं कागजों से मिलती है जैसे की परफ्यूम लगे कागज के फूलों से जितनी खूशबू आती है इस कारण असली फूलों को कोई सूंघता नहीं है ।

बहस में हमेशा मौन रहने वाले शालीन भैया ने मुंह खोला और बोले आप सभी कागज की औकात को चुनौती मत दो, कागजी लिखा पढ़ी और कागजीपन पुरस्कार, अवार्ड प्रसिद्धी सिद्धी, इज्जत, पेंशन, पद आदि दिला देते हैं फिल्मी गानों और मूवी में रुचि रखने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण जी बोले मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, यह कोरा कागज की ही देन है। कागज पर तो कई फिल्में बनी है। कागज के फूल, कोरा कागज, प्यार के कागज पर कागज, स्याही कलम के गीत लिखे गए हैं। प्यार के कागज पर दिल की कलम से मेरे महबूब के नाम खत लिखा! यह सब कागज पर ही चलती है और कागज पर ही खत्म होती है। इस पर कागजों पर लिख लिख कर और अप्रकाशित रचनाओं से साहित्यकार बजने वाले प्रोफेसर अकिंचन जी बोले जब मैं कागज पर रचनाएं लिखता हूं तो श्रीमती किचन में से आवाज लगती है क्यों कागज काले कर रहे हो, छपते वपते तो नहीं हो, लिख लिख कर पूरा जीवन कोरा कागज बना लिया। जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। कागज पर कभी कविता फविता, कभी गजल वजल, कभी लेख वेख कभी रिपोर्ट विपोर्ट, कभी समीक्षा दीक्षा लिखी और जब नहीं छुप पाई तो लिखे कागज कोरे ही माने जाने लगे। तुम्हारे लेखन में दम नहीं है और कागज को यूं ही बदनाम कर कभी कागज को कोरा तो कभी कागजों को काला करना बता रहे हो। जबकि कागज अपनी तासीर के मुताबिक सड़के, तालाब, नल, स्टाप डेम, बिल्डिंग स्कूल बनाते है इनको बनवाने वाले कागज पर ही इन्हें बना हुआ बताकर खुद गांधी जी की तस्वीर वाले कागज खिसिए में भर लेते हैं और कहते हैं कि सड़क तालाब कागजी बना लिए, इसमें कागज का कोई लेना-देना नहीं फिर भी कागज यूं हीं बदनाम हो जाते हैं !

पंडित जी बोले शायरों ने भी कागज पर बहुत कुछ लिखा। एक शायर ने तो कागज की महत्ता बताते हुए लिखा कि कागज पर लिखी गजल काजल बकरी चबा गई/ चर्चा पूरे शहर में हुई कि एक बकरी शेर खा गई ! इस तरह कागज शेर से कम नहीं है, कागज में सरकार चलाने ,गिराने की ताकत होती है कागज में जो दस्तावेज होते हैं जो अच्छे-अच्छे को दस्त लगा देते हैं पर ऐसे कागजों को यूं ही बदनाम कर रखा है जो अवाम के लिए आगाज है!

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

शब्दों की फिजूल खर्ची कोई अच्छी बात नहीं.....

यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर समय हर किसी विषय पर बोला ही जाए। हालांकि मौन एक प्रकार से सहमति सूचक भी होता है। लेकिन फिर भी इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकाला जा सकता। यह एक तटस्थ भाव प्रकट करता है। जिंदगी में कुछ एक अवसर ऐसे भी आते हैं जब मुखर रहने पर बात बढ़ जाती है और मौन रहने पर बात सध जाती है। इस अर्थ में मौन एक सार्थक अभिव्यक्ति है। कभी-कभी तो मौन की मुखरता इस कदर प्रखर होती है कि शब्द भी बौने पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम अंतर्मन की भावनाओं के वेग पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, जिंदगी में तमाम तरह के विवादों से अपने आप को परे रख सकते हैं। अन्यथा मुखर रहने के चलते अपने ही शब्द संसार में उलझ कर रह जाना होता हैं। अनेक अवसर ऐसे भी आते हैं जब हम बिना सोचे समझे अनर्गल प्रलाप कर बैठते हैं। चाहे ऐसा प्रलाप किसी अन्य के विरुद्ध न हो, लेकिन फिर भी सुनने वालों के मानस पटल पर विपरीत प्रभाव छोड़ता है।

मारे अंतर्मन में निरंतर अनेक तरह के विचार उदय में आते हैं। इनमें से कुछ एक विचारों को किसी से साझा करना हम उपयुक्त समझते हैं। ऐसे विचारों को शाब्दिक जामा पहना कर हम औरों के सामने प्रकट करते है। जिसकी सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आती है या सुनने वालों के मन में हमें लेकर कोई अवधारणा घर कर जाती है। यह सिलसिला जिंदगी भर यूं ही चला करता है। इसके चलते जनसाधारण या व्यक्ति विशेष के मानस पटल पर हमारी छवि अंकित होती है। दरअसल आदमी कुल मिलाकर क्या है ? इसका पता जमाने को तब चलता है जब आदमी अपना मुंह खोलता है। हालांकि बोलना सब जानते हैं लेकिन कब, कहां, कैसे और क्या बोलना ? इसे लेकर बहुत कम लोग सतर्क रह पाते हैं।

दरअसल हमें अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व को घड़ने में समय-समय पर कहे गए शब्दों का अहम योगदान होता है। लेकिन कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में मौन रहना भी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर समय हर किसी विषय पर बोला ही जाए। हालांकि मौन एक प्रकार से सहमति सूचक भी होता है। लेकिन फिर भी इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकाला जा सकता। यह एक तटस्थ भाव प्रकट करता है। जिंदगी में कुछ एक अवसर ऐसे भी आते हैं जब मुखर रहने पर बात बढ़ जाती है और मौन रहने पर बात सध जाती है। इस अर्थ में मौन एक सार्थक अभिव्यक्ति है। कभी-कभी तो मौन की मुखरता इस कदर प्रखर होती है कि शब्द भी बौने पड़जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम अंतर्मन की भावनाओं के वेग पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, जिंदगी में तमाम तरह के विवादों से अपने आप को परे रख सकते हैं। अन्यथा मुखर रहने के चलते अपने ही शब्द संसार में उलझ कर रह जाना होता हैं। अनेक अवसर ऐसे भी आते हैं जब हम बिना सोचे समझे अनर्गल प्रलाप कर बैठते हैं। चाहे ऐसा प्रलाप किसी अन्य के विरुद्ध न हो, लेकिन फिर भी सुनने वालों के मानस पटल पर विपरीत प्रभाव छोड़ता है। चाहे हमने अपनी वाणी से किसी का अहित न भी किया हो तब भी हमारे अन्तस की भावनाओं का प्रकटीकरण हमें लेकर नकारात्मक भाव उत्पन्न करा सकता है। बोलचाल में प्रयुक्त शब्दावली हमारे अंतर्मन के आंतरिक चरित्र का दिग्दर्शन कराती है।

वास्तव में हर आदमी का प्रतिक्रियावादी स्वभाव होता है। यह अलग बात है कि ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की गई हो या नहीं। किसी क्रिया की प्रतिक्रिया करने पर एक प्रकार से हम बेनकाब हो जाते है। हमारा वैचारिक दृष्टिकोण जग जाहिर हो जाता है। जिसके चलते जमाने में अलग-अलग तरह के आदमी अलग-अलग तरह के अर्थ निकाल लेते हैं। या कि हमें लेकर कोईधारणा बना लेते हैं या उनके मन में हमें लेकर कोई ग्रंथि बन जाती है। दरअसल अध्यात्म की दृष्टि से शब्द को ब्रह्मस्वरूप माना गया है। इसलिए हर एक शब्द का कुछ न कुछ परिणाम निकलता है।

ऐसा नहीं है कि हमने मन की भावना उजागर की तो उसकी कहीं कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होगी। दरअसल उच्चारित शब्द अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं। वास्तव में विज्ञान के ज्ञान की भांति हर क्रिया की प्रतिक्रिया सहज स्वाभाविक होती है। कभी-कभी भावावेश में सर्वथा अनर्गल एवं आपत्तिजनक शब्दावली का उपयोग तो हमारे चरित्र पर ही लांछन लगा देता है। जिसके चलते हमारे व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम संयमित एवं संतुलित शब्दावली का उपयोग करते हुए अपने भाव अभिव्यक्त करते रहें। विवादित विषयों पर कूदकर कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। अन्यथा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का परिणाम सर्वथा नकारात्मक रूप से भी सामने आ सकता है। दरअसल शब्दों का अपव्यय करने सेहमारे ही शब्द हम पर ही भारी पड़ जाते हैं। जिसकी खानापूर्ति सहज संभवनहीं होती।

दरअसल शब्दों की फिजूलखर्ची कभी-कभी तो वैचारिक दृष्टि से कंगाल बना देती है। वैसे कुछ लोगों का जीवन खुली किताब की तरह रहता है। जिसके चलते मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति करने में वे रत्ती भर भी देर नहीं करते। व्यवहार में देखा गया है कि अनेक अवसरों पर वह व्यर्थ ही विवादों के घेरे में आ जाया करते हैं। इन संदर्भों में यह आवश्यक है किजब हम बोले तो तोल मोल कर बोले। अन्यथा नहीं बोले। प्रयास रहे कि कभी हमारे ही शब्द हम पर ही भारी न पड़ जाए। दरअसल हमें अपने व्यक्तित्व को अनुकरणीय आदर्श के रूप में ढालने के लिए अभिव्यक्ति के स्वरूप को सही दिशा देने की जरूरत है।

प्रदूषण पर चर्चा

राज कुमार सिन्हा

बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ

हवा की सांसें उखड़ने लगीं और हम चुप हैं

सबसे गंदी हवा वही लोग सांस में लेते हैं जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं,गरीब परिवार, सड़क किनारे रहने वाले लोग, औद्योगिक क्षेत्रों के पास बसे समुदाय और मेहनतकश मजदूर। सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, सीओपीडी, खांसी, ब्रोंकाइटिस अब हर घर की सामान्य शिकायत बनती जा रही हैं। दिल और दिमाग पर इसका प्रभाव और भी घातक है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण रक्त में घुलकर दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा देते हैं। वायु प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार बच्चों पर पड़ती है। उनके विकसित होते फेफड़े प्रदूषित हवा सहन नहीं कर पाते, जिससे जीवनभर के लिए फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी अत्यधिक जोखिम में रहती हैं, क्योंकि उनकी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता हवा में मौजूद सूक्ष्म विषैले कणों से प्रभावी ढंग से लड़ नहीं पाती।

वायु प्रदूषण आज हमारे समय का सबसे मौन लेकिन सबसे घातक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। शहर हों या गांव, हर जगह हवा में घुले अदृश्य जहरीले कण, जैसे औद्योगिक धुआं, वाहनों का उत्सर्जन, थर्मल पावर प्लांटों की राख और घरेलू ईंधन का धुआं लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहे हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि लोग बिना शोर-शराबे के बीमार हो रहे हैं। न इसका दर्द तुरंत दिखता है, न इसकी मार तत्काल महसूस होती है, लेकिन शरीर को भीतर से खोखला करने की इसकी क्षमता बेहद तेज है। आज हवा में घुला जहर केवल पर्यावरण संकट नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर चल रहा एक धीमा हमला है।

वायु प्रदूषण को रोकना अब केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं रहा,यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति बन चुका है। वायु प्रदूषण सिर्फ स्वास्थ्य की समस्या नहीं, यह सामाजिक असमानता का आईना भी है। सबसे गंदी हवा वही लोग सांस में लेते हैं जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं,गरीब परिवार, सड़क किनारे रहने वाले लोग, औद्योगिक क्षेत्रों के पास बसे समुदाय और मेहनतकश मजदूर। सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, सीओपीडी, खांसी, ब्रोंकाइटिस अब हर घर की सामान्य शिकायत बनती जा रही हैं। दिल और दिमाग पर इसका प्रभाव और भी घातक है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण रक्त में घुलकर दिल का दौरा, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा देते हैं। वायु प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार बच्चों पर पड़ती है। उनके विकसित होते फेफड़े प्रदूषित हवा सहन नहीं कर पाते, जिससे जीवनभर के लिए फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है।

बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी अत्यधिक जोखिम में रहती हैं, क्योंकि उनकी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता हवा में मौजूद सूक्ष्म विषैले कणों से प्रभावी ढंग से लड़ नहीं पाती।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के जलवायु, पर्यावरण और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, वायु प्रदूषण से हर साल विश्व में लगभग 90 लाख मौतें होती हैं। नवंबर में प्रकाशित लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में 17 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुईं। यह संख्या 2010 की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 7.5 लाख मौतों के लिए जीवाश्म

ईंधन जिम्मेदार है। अकेले कोयले से लगभग 4 लाख मौतें हुई हैं। वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन से जुड़े वायु प्रदूषण के कारण 25.2 लाख मौतें दर्ज की गईं। ये निष्कर्ष ऐसे समय में आए हैं जब दिल्ली और उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा फिर से घने शीतकालीन धुंध की चपेट में है।दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 के पार पहुंच चुका है। कई इलाकों में पीएम 2.5 स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तय सुरक्षित सीमा से 20 गुना अधिक दर्ज किया गया है।

हरियाणा में वायु प्रदूषण के कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी के मामलों में वृद्धि देखी गई है।

पीजीआई रोहतक की गायनी विभाग की अध्यक्ष डॉ. पुष्पा दहिया के अनुसार,एक वर्ष में 13,500 डिलीवरी हुई है।

इनमें से 18 प्रतिशत (2,430 बच्चे) प्रीमेच्योर जन्मे हैं। इसका प्रमुख कारण प्रदूषण बताया गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा कोयला खदानों के पास रहने वाले 1,202 लोगों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि

14.3 प्रतिशत श्रमिकों,10 प्रतिशत पर्यवेक्षक कर्मचारियों और 7.8 प्रतिशत स्थानीय निवासियों के फेफड़ों का कार्य असामान्य था। एक्स-रे में फेफड़ों में फाइब्रोसिस के मामले भी सामने आए हैं।

भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कानून मौजूद हैं।वायु (रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निगरानी और कार्रवाई की शक्तियां दी गई हैं।2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) देश का सबसे बड़ा केंद्र-स्तरीय प्रयास है, जिसका लक्ष्य 131 शहरों में पीएम 10 स्तर को 40 प्रतिशत तक कम करना है। हालांकि, 2019-2025 के बीच जारी 11,211 करोड़ रुपये में से केवल 68 प्रतिशत (7,594 करोड़ रुपये) का ही उपयोग हो पाया है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 29 जिला मुख्यालयों की हवा पिछले वर्ष की तुलना में और खराब हुई है। इसमें इंदौर जैसे 'स्वच्छ शहर' भी शामिल हैं। आदिवासी बहुल जिलों अलीराजपुर, डिंडोरी, उमरिया, बैतूल में भी एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 131 शहरों को नॉन-अटेनमेंट (वायु गुणवत्ता का अनुपालन नहीं करने वाला शहर) सिटी घोषित किया है। मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और देवास इस सूची में शामिल हैं। राज्य सरकार ने शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए नगर वन योजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है, जिसके तहत पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।लेकिन दूसरी ओर,भोपाल में 27,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव विरोध के बाद रद्द हुआ।अयोध्या बायपास विस्तार के लिए 8,000 पेड़ों की कटाई पर विरोध। जबलपुर, सागर, रायसेन और मंडला में अवैध या नियम विरुद्ध पेड़ कटाई के मामलों पर हाईकोर्ट और एनजीटी को हस्तक्षेप करना पड़ा है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरणीय संतुलन लगातार नज़र अंदाज किया जा रहा है।

उद्योग, शहरीकरण और उपभोग को अनियंत्रित रूप से बढ़ाते हुए हमने हवा, पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित कर दिया है। वायु प्रदूषण अब भविष्य की नहीं, आज की आपदा है। अगर संसद, सरकार और समाज ने इसे स्वास्थ्य आपातकाल की तरह नहीं लिया, तो इसकी कीमत हमें सांसों से चुकानी पड़ेगी।

अनोखे गांव

ब्रजेश कानूनगो

लेखक साहित्यकार हैं।

नहरों से जुड़े घर और सुंदर बस्तियां

कस्बे में एक खूबसूरत तुधोप पार्क है। मीठे पानी की झील के किनारे यहां एक बीच भी है। रविवार को छुट्टी होने से बच्चों और परिवारों की उपस्थिति ज्यादा थी। बॉलीवाल, स्केटिंग, नौकायन, तैराकी,वाटर स्पोर्ट्स आदि यहां झीलों के किनारे होने वाली आम गतिविधियां होती हैं। लोग बारबेक्यू जमाये खाने-पीने में भी व्यस्त थे। रेत पर घर बनाते और खेलते बच्चों के अलावा कुछ दिव्यांगजन भी अपने विशेष वाहनों पर पार्क का आनन्द उठाते नजर आए। कुछ लाइफ गार्ड्स भी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं देते दिखाई दिए।

नितिया में कई ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां सड़कों की बजाय नहरों में बोटिंग से एक घर से दूसरे घर जाया जाता है। गिथोर्न नीदरलैंड का एक ऐसा ही छोटा सा गांव है, जो अपनी सुंदर नहरों, पुलों और घास के छत वाले घरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 'नीदरलैंड का वेनिस' भी कहा जाता है। गांव में कोई सड़क नहीं है, और लोग नाव, साइकिल या पैदल ही यात्रा करते हैं।

पिछले दिनों हमने ट्रैवलर बंसी बिश्नोई के यूट्यूब वीडियो से नीदरलैंड के इसी कस्बे गिथोर्न की मानस यात्रा की। खूबसूरत और अनोखे गिथोर्न में कोई 176 पुल हैं जिनके नीचे से नावें और बोट निकलकर हरेक घर तक पहुंच सकती हैं।, सड़कों की जगह नहरें कस्बे के यातायात का माध्यम बनती हैं। गांव के घरों की छतें घास से बनी हुई हैं, जो उन्हें एक अनोखा और सुंदर रूप देती हैं। गांव में नाव और साइकिल किराए पर ली जा सकती हैं, जो पर्यटकों केलिए एक अच्छा विकल्प हो जाता है।

ट्रैवलर के वीडियो को देखते हुए हमें अपने कनाडा प्रवास में देखे ऐसे हीएक नहरों के जरिए जुड़े एक गांव की स्मृति हो आई। कनाडा प्रवास के दौरान हम लोग न्यूमार्केट कस्बे में हमारे घर से कोई 70 किलोमीटर दूर स्थितओरिलिया कस्बे की वृहद झील पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे। कस्बे में एक खूबसूरत तुधोप पार्क है। मीठे पानी की झील के किनारे यहां एक बीच भी है। रविवार को छुट्टी होने से बच्चों और परिवारों की उपस्थिति ज्यादा थी। वॉलीवाल, स्केटिंग, नौकायन, तैराकी,वाटर स्पोर्ट्स आदि यहां झीलों के किनारे होने वाली आम गतिविधियां होती हैं। लोग बारबेक्यू जमाये खाने पीने में भी व्यस्त थे। रेत पर घर बनाते और खेलते बच्चों के अलावा कुछ दिव्यांगजन भी अपने विशेष वाहनों पर पार्क का आनन्द उठाते नजर आए। कुछलाइफ गार्ड्स भी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं देते दिखाई दिए।

नेताओं और महान व्यक्तियों की स्मृति और युद्ध में गौरव पूर्ण विजय को यादगार बनाने के लिए अनेक स्मारक हम देखते

ही रहे हैं। लेकिन ओरिलिया कस्बे के तुधोप पार्क में कनेडियन श्रमिकों के उनके अवदान और कार्य करते हुए अपनी जान गंवा देने को सम्मान व महत्व देने के लिए बने स्मारक को देखकर विशेष खुशी का अहसास हुआ।

कनाडा की लबालब झीलों और पार्कों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये सुंदरहैं। व्यवस्थित हैं। साफ सुथरे और सुविधा सम्पन्न हैं। प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव को यहां अनुभव किया जा सकता है। लोगों की रुचियों और जीवन शैली को अनुशासित ढंग से एक सूत्र में बांधे हुए आनन्द की हिलोरेंयहां सर्वत्र दिखाई देती हैं। यह अद्भुत है और अनुकरणीय भी। औरेलिया से ही कोई दस मिनट की ड्राइव के बाद एक विशिष्ट और खूबसूरत 'लगून सिटी' पहुंचे। इस खास बस्ती की विशेषता यह है कि यहां के प्रत्येक घर और कॉटेज के सामने या पीछेझील से जुड़ी नहरें इस तरह गुजरती हैं, जैसे हमारे यहां सड़कें बनी होती हैं। बेशक इन घरों के सामने सड़क तो है ही लेकिन नहरों के जरिये अपनी बोट से,नाव से भी यात्रा की जा सकती है। निकट के शहर भी जाया जा सकता है और झील में पहुंच कर वाटर स्पोर्ट्स, बीच आदि का आनन्द भी उठाया जा सकता है।

बहती नहरों के ऊपर कई ऊंचे ब्रिज बने हैं जिनसे वाहन गुजरते हैं और नीचे से बड़े छोटे जल यान, मोटर बोट्स और नावों में यहां के निवासी यात्रा करते हैं। आनन्द उठाते हैं। घरों के नीचे तक पानी इस तरह भरा होता है कि बोट्स आदि कारों की तरह घर में पार्क भी किये जा सकते हैं। इस नए दृश्य और जीवन

शैली को देखना हमारे लिए बहुत रोमांचक रहा था। ट्रैवलर बंसी बिश्नोई के नीदरलैंड यात्रा में गिथोर्न गांव के यूट्यूब वीडियो ने हमारे देखे कनाडा के लगून सिटी के सारे अनूठे अनुभव पुनः ताजा कर दिए।

दुनिया भर में अनेक ऐसे शहर और गांव हैं जो झीलों और खूबसूरत नदियों, समुद्र की जलराशि के बीच पर्यटकों और घुमक्कड़ों को लुभाते रहें हैं। इटली के वेनिस को तो हर कोई जानता है जो एक प्रसिद्ध शहर है और नहरों पर बना हुआ है। चीन का गियानजियांग भी ऐसा ही एक छोटा सा गांव है नीदरलैंड का अम्स्टर्डम एक प्रसिद्ध शहर है जहां नहरों का अपना विशेष महत्व है। इसी तरह जापान का कागोशिमा शहर भी नहरों पर बना हुआ है। यहाँ के घरों में भी बोटिंग के लिए विशेष व्यवस्था है और लोग बोट से ही एक घर से दूसरे घर जाते हैं।

भारत में पूरी तरह नहरों का सौंदर्य समेटे ऐसा कोई विशेष गांव या हिस्सा तो नहीं हैं जहां नहरों में हर घर से बोटिंग की जाती है। किंतु बहुत सी ऐसी जगहें अवश्य हैं जहां का अनुभव भी कम स्मरणीय नहीं होता। कश्मीर की डल झील और उदयपुर की पिछोला झील, भोपाल का बड़ा तालाब और केरल के बेक वाटर, उत्तर पूर्व और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र सहित देश भर में कई छोटे बड़े गांव जो टापुओं पर मुख्य आबादी से अलग बसे हैं वहां की यात्रा थोड़ा बहुत इस रोमांच और जीवनशैली का अहसास करा ही सकती है, लेकिन पूरी तरह नहरों पर बसी कनाडा की लगून सिटी और नीदरलैंड के गिथोर्न गांव की मोहकता और अनूठेपन की तो बात ही कुछ अलग है।

Mantra Of Success-

राजेश शर्मा

वैष्णवी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित हो कर बढ़ाया ग्वालियर का मान, मुस्कुराया देश का दिल मप्र

'क

हिए तो आसमां को
ज़मीं पर उतार लाएं
मुश्किल नहीं है
कुछ भी अगर ठान लीजिए'

महज 19 बरस की उम्र में वैष्णवी शर्मा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयनित हो कर ग्वालियर ही नहीं वरन् मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है। संगीत सम्राट तानसेन की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर की बिटिया वैष्णवी शर्मा ने मलेशिया में अंडर -19 महिला टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में पदार्पण में हैट्रिक लेकर इतिहास रच डाला था उसी दिन से इस नन्ही प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा के दर्शन करा दिये थे कि यह संभावनावान क्रिकेटर भारतीय महिला क्रिकेट टीम में दस्तक दे रही है।

महज 4 बरस की नन्ही उम्र से क्रिकेट का सफर, राह में कई चुनौतियां थी पर वह तो बनी थी क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट के लिए... जुनून ऐसा कि चौबीसों घंटे बस क्रिकेट- क्रिकेट और क्रिकेट। आंखों में सपना लिए कि एक दिन इंडिया टीम के

लिए खेलना है आखिरकार 4 बरस की उम्र से जो सुनहरा सपना देखा था आज वह साकार हो गया।

अथक संघर्ष से सफलता के सफर तक के कदम, उपलब्धियों से भरे ये पल । सच में सपने साकार होने के पल है। गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास को समाहित किए ग्वालियर नगरी की बिटिया यशस्वी की इस उपलब्धि से मानों इस ऐतिहासिक नगरी का स्वर्णिम इतिहास फिर से जीवंत होने जा रहा है और इस अध्याय को लिखा है यशस्वी ने । 19 बरस की इस प्रतिभाशाली क्रिकेटर ने अपनी असाधारण उपलब्धि से देश के दिल मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है। जिद-जुनून और जज्बे की कहानी है वैष्णवी की। आसमान छूने का हौसला रख आज यह बिटिया हर युवाओं के लिए यूथ आईकन है।

वैष्णवी तुम्हारी उपलब्धियों पर मध्यप्रदेश को नाज है, मुस्काया देश का दिल मध्यप्रदेश....

अंडर -19 महिला टी-20 वर्ल्ड कप में पदार्पण में हैट्रिक लेकर वैष्णवी ने रचा था इतिहास... 'भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हमारे ग्वालियर की बेटी वैष्णवी शर्मा के चयन पर मैं अत्यंत उत्साहित और गौरवान्वित हूँ। तुम्हें हृदय से ढेरों बधाई और शुभकामनाएँ बेटा। वैष्णवी, तुम्हारी मेहनत, अनुशासन और सपनों के प्रति समर्पण ने न केवल परिवार, बल्कि पूरे ग्वालियर-चंबल अंचल का मान बढ़ाया है। मुझे विशेष हर्ष है कि ग्वालियर की मिट्टी से निकली यह उज्ज्वल प्रतिभा अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तुम्हारा सफ़र नई सफलताओं और गौरवमय उपलब्धियों से जगमगाता रहे, हार्दिक शुभकामनाएँ।'

ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया केंद्रीय संचार मंत्री, भारत सरकार

'वैष्णवी शर्मा का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन से हम सभी ग्वालियरवासी बहुत खुश है, बिटिया मध्यप्रदेश सहित पूरे देश को आप पर गर्व है। मुझे वो दिन भी याद है कि वैष्णवी बोलती थी कि चाचा जी आप पापा जी को बोल दो वो मेरी ज्यादा चिंता करते है, में निश्चित ही भारत की महिला क्रिकेट टीम में खेलूंगी। आज वो शब्द अक्षरशः सही साबित हुए। वैष्णवी को बधाई'

- डॉ. नितेश शर्मा, प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश

धार विधानसभा स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया

धार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुरूप एवं क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट के अपने साकार करने एवं खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 15 अक्टूम्बर से 25 दिसम्बर के मध्य किया जाना है। विधानसभा धार क्षेत्रान्तर्गत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 17 दिसम्बर को 8 खेलों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, व्हॉलीबाल का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण जेतपूरा, कबड्डी खेल-शासकीय पी.जी.कॉलेज धार, खो-खो खेल-शासकीय आर्दश आवासीय विघालय माण्डु रोड़ धार, कुश्ती खेल-एसपीडीए हॉल धार, बास्केटबाल-डीआरपी लाईन धार में किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विधानसभा क्षेत्र धार के चयनित खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगें। सांसद खेल महोत्सव के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष महंत निलेश भारती, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदारसिंह मेड़ा, भाजपा जिला महामंत्री देवेन्द्र सोनोने ने खेल प्रतिभागी खिलाड़ियो को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा जिला खेल और युवा कल्याण विभाग अधिकारी राजेश शाक्य, बीईओ विष्णु गुप्ता पुरुषोत्तम दुबे मंडल महामंत्री अमित शर्मा जीवन यादव पंकज जाधव समेत जनजातीय कार्य विभाग, शिक्षा विभाग, सांई सेंटर, खेल संघ संस्था धार के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें। कार्यक्रम का संचालन राजेश डाबी व आभार अनिरुद्ध चावड़ा ने माना।

अभा अग्रवाल युवक- युवती परिचय सम्मेलन के लिए अग्रबन्धुओं में भारी उत्साह

● लेबड़, घाटाबिलोद,सहित महू में अग्रबंधुओं के घर जाकर कर किया प्रचार प्रसार

धार। मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा धार द्वारा अग्रवाल समाज धार के सानिध्य में दो दिवसीय अखिल भारतीय विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन धार स्थित श्रद्धा,शगुन गार्डन में 10 एव 11 जनवरी को होगा।जिसको लेकर अग्रबन्धुओ, महिलाओ में भारी उत्साह देखा जा रहा है। परिचय सम्मेलन को लेकर गठित दल प्रतिदिन अलग-अलग जगह-जाकर अग्रबन्धुओ से परिचय सम्मेलन के लिए विवाह योग्य बालक एवं बालिकाओं की एंट्री प्राप्त कर सम्मेलन का प्रचार प्रसार कर रहे है।

सोमवार को परिचय सम्मेलन समिति के मुकेश अग्रवाल,बबीता अग्रवाल, जितेंद्र अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, पायल गोयल लेबड़, घाटाबिलोद होते हुए महू पहुँचे साथ ही धार नगर के लिए अर्पणा अग्रवाल, दीपा अग्रवाल,संदीप अग्रवाल,क्रिश अग्रवाल,स्मिता अग्रवाल, नीतू अग्रवाल,अशोक गर्ग,कविता गर्ग,सरोज गोयल,मेघा गोयल ने अग्रबन्धुओ के घर- घर जा कर प्रचार प्रसार किया ओर बड़ी संख्या में विवाह योग्य युवक युवतियों की एंट्री प्राप्त की। जानकारी मीडिया प्रभारी अशोक मित्तल एवं श्याम मंगल लेबड़ ने दी।

खुले केन्द्रों से धान परिवहन की रफ्तार धीमी, सीमित क्षमता के कारण बढ़ रही अव्यवस्थाएं

बैतूल। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य जारी है। लेकिन मिल मालिकों और शासन के बीच धान प्रोसेसिंग के लिए अभी तक अनुबंध नहीं हो सका है। नतीजा यह कि खरीदी तो शुरू हो गई, लेकिन धान का उठाव नहीं हो रहा है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में खुले धान खरीदी केन्द्रों से गोदामों तक परिवहन शुरू कर दिया है, लेकिन परिवहन की रफ्तार धीमी होने की वजह से शुरुआती चरण में ही भंडारण का संकट होने लगा है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023-24 में मिलरों राशि दी जाती थी, लेकिन इस बार नीति में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा शर्त रखी गई है कि 60 प्रतिशत धान एफसीआई में जमा करनी होगी और केवल 40 प्रतिशत हिस्सा मिलरों को मिलेगा। यदि 60 प्रतिशत से कम धान एफसीआई को जाती है तो कटौती सीधे मिलर की अमानत राशि से की जाएगी। यही नियम मिल मालिकों की नाराजगी का मूल कारण बना हुआ है। नई नीति को लेकर मिल मालिकों ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा कि इन शर्तो के साथ वे अनुबंध नहीं कर सकते। नतीजा यह हैं कि मिल मालिकों और शासन के बीच धान प्रोसेसिंग के लिए अभी तक अनुबंध नहीं हो पाया है। अनुबंध नहीं होने से धान का परिवहन नहीं हो पा रहा है। ज्यादा दिक्कते उन केन्द्रों पर हो रही है, जहां पर धान की खुले में खरीदी की जा रही है और खरीदी केन्द्र पर किसानों को भी परेशान होना पड़ रहा है।

कंपनियों से एफआरके खरीदने की बाध्यता -

मिलिंग एजेंसी द्वारा चावल के साथ मिलाए जाने वाले एफआरके की सप्लाई के लिए कुछ कंपनियों को चयनित किया गया है, जिसमें मिलर्स को उन्हीं कंपनियों से एफआरके खरीदने के लिए बाध्यता है है जिसका भुगतान मिलर्स द्वारा ही किया जाना है। नीति समय-समय में राईस मिल भौतिक सत्यापन के लिए लिखा गया है, किन्तु वास्तविकता में मिलर्स को प्रदाय धान से निर्धारित अनुपात के अनुसार चावल की प्राप्ति नहीं होने के कारण भौतिक सत्यापन के समय स्टॉक में अंतर आता है,

मिल मालिकों और शासन के बीच अनुबंध नहीं

जिसके कारण मिलर्स मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

लोडिंग-अनलोडिंग का भुगतान संबंधित आदेश जारी नहीं - बताया जा रहा है कि बैतूल जिला के पूर्व वर्षों में सीएमआर का शॉट-फॉल जिला रहा था जिस आधार पर संपूर्ण सीएमआर स्टेट पूल में जमा कराना होता था परंतु इस वर्ष चावल का रेशो कम होने के कारण बैतूल जिला एफआईसी के अंतर्गत आ रहा है, जिस कारण बिना अपग्रेडेशन राशि के एफसीआई में काम करना असंभव होगा। वहीं वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में की गई मिलिंग के अंतर्गत मिलर्स को धान चावल की लोडिंग अनलोडिंग का भुगतान किए जाने संबंधी आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए है। उपार्जन वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में उपार्जन के लिए समितियों में जमा की गई बोरियों पर राज्यांश की उपयोगिता व्यय राशि का भुगतान किए जाने आदेश आज तक जारी नहीं। गए है, जिसकी वजह से उक्त मिलर्स को अप्राप्त है।

अभी तक 1 लाख 49 मेट्रिक टन धान की खरीदी - जिले में 1 दिसंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू हुआ है और अभी तक 1 लाख 49 हजार मेट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। जिले में धान खरीदी के लिए 20 केंद्र बनाए गए है, जिनमें 16 गोदाम आधारित है, जहां भंडारण समस्या अपेक्षाकृत कम है, वहीं चोपना क्षेत्र के चार केंद्रों में खुले में धान खरीदी की जा रही है। हालांकि यहां से विभाग द्वारा धान का परिवहन कराया जा रहा है, लेकिन धान परिवहन की रफ्तार धीमी है। इन केन्द्रों की क्षमता सीमित होने से पूरी व्यवस्था अव्यवस्था में बदलते जा रही है। बताया जा रहा है कि किसानों की उमड़ती भीड़ और लगातार बढ़ रहे खरीदी दबाव के बीच शासन-मिलरों का विवाद अगर जल्द नहीं सुलझा, तो धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया अव्यवस्था और नुकसान में बदल सकती है और इसकी सीधी मार किसानों पर पड़ेगी।

इनका कहना है -मिल मालिकों से अभी तक अनुबंध नहीं हुआ है। मिल एसोसिएशन की मिल नीति को लेकर कुछ मांगें हैं, जिनको लेकर उन्होंने शासन को ज्ञापन सौंपा है। शासन स्तर से ही मामले में निर्णय होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। फिलहाल जहां खुले केन्द्रों पर धान खरीदी हो रही है, वहां से परिवहन कार्य शुरू कर दिया है। अभी तक 1 लाख 49 हजार एमटी धान की खरीदी हो चुकी है।

-जीएल लुधियानवी, डीएमओ नागरिक आपूर्ति निगम बैतूल

तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, दो युवकों की मौत

बैतूल। बैतूल-सारणी स्टेट हाईवे के ग्राम चिखलार के पास मंगलवार देर रात एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतकों की पहचान मुकेश पिता गुलाब वरवड़े (30) और मुकेश पिता पतंग चौकीकर (32) के रूप में हुई है। तीसरा युवक रविकुमार गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की 112 टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित किया। शवों का पोस्टमॉर्टम बुधवार सुबह जिला अस्पताल में किया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार, मुकेश चौकीकर कैटरिंग का काम करते थे, जबकि मुकेश वरवड़े पेंटिंग का कार्य करते थे। दोनों रात को चिखलार गए थे और लौटते समय हादसा हुआ। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच जारी है।

फांसी के फंदे पर लटका मिला अधेड़ का शव

बैतूल। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोदारोटी में एक व्यक्ति (48) का शव उसके घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान दीना पिता डोमा धुर्वे (48) निवासी ग्राम कोदारोटी के रूप में हुई है। परिजनों ने मंगलवार शाम दीना को घर में फांसी पर लटका देखा, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा और पंचनामा कार्रवाई पूरी की। परिजनों के मुताबिक जिस समय फांसी लगाई, घर के लोग खेत पर गए हुए थे। लौटने पर उसे घर के पिछले हिस्से में फांसी पर लटके देखा।इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

युवा संगम के तहत रोजगार मेला 24 दिसंबर को

बैतूल। मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार विभाग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 24 दिसंबर को युवा संगम के तहत रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन प्रातः 11 से 4 बजे तक शासकीय डॉ.भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय आमला में किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन ने कार्यक्रम आयोजन का नोडल जिला रोजगार अधिकारी और प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य विभागीय अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का प्राथमिकता के आधार पर निर्वहन एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके।

सीएमएचओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडारा एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खेडला का किया निरीक्षण

बैतूल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाडे ने 16 दिसम्बर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खंडारा एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खेडला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केन्द्र खेडला में सीएचओ एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनुपस्थित मिले। दोनों अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन आहरण नहीं करने के आदेश बीएमओ सेहरा को दिए गए एवं कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। संतोषप्रद जवाब न देने पर दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। साथ ही सीएमएचओ द्वारा ग्राम में टीकाकरण सत्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में महिलाओं से चर्चा कर ग्राम में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। सीएमएचओ ने महिलाओं को बताया कि जन्म प्रमाण-पत्र एवं टीकाकरण कार्ड एक बहुत ही

महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो हमेशा बच्चे के काम आएगा, इसे संभाल कर रखें। उन्होंने बताया कि बच्चों को सही उम्र टीके लगाया जाना कितना आवश्यक है, धात्री महिलाओं को बताया कि 6 महीने तक बच्चों को मां के दूध के अतिरिक्त ऊपरी आहार कुछ नहीं देना है, मां का दूध अमृत के समान एवं सर्वोत्तम है। उन्होंने शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर डाटा मैनेजर तापीदास चढ़ोकार भी उपस्थित रहे।

पुलिस ने चाकूबाजी के 3 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार

बैतूल। पुलिस ने चाकूबाजी के 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 6 जुलाई को फरियादी दानिश कुरैशी पिता जावेद कुरैशी उम्र 15 साल निवासी तिलक वार्ड कोठी बाजार बैतूल ने हमराह शेख सरीफ कुरैशी ने रिपोर्ट किया कि 5 जुलाई के रात्रि करीबन 11.50 बजे अपने दोस्त रजा कुरैशी एवं जैद कुरैशी के साथ इमामबाडा आजाद वार्ड में बाबा की सवारी में नाच रहे थे, नाचने के दौरान रजा कुरैशी के हाथ का धक्का निहाल एवं रिजु को लगा तो इसी बात को लेकर निहाल एवं रिजु हम तीनों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे जो सुनने में बुरी लग रही थी। गाली देने से मना किया तो निहाल ने रजा के दोनों हाथ पकड लिया और रिजु ने अपने पास रखा चाकू निकालकर रजा कुरैशी के ऊपर दो-तीन वार किये, जिससे रजा कुरैशी को कमर व पेट के बाये हिस्से में चोटे आई है। बीच बचाव करने पर निहाल एवं उसका साथी तालीफ ने मुझे और जैद को हाथ मुक्को से मारा। जिससे बांये गाल पर मूंदी चोटे एवं जैद को दाहिने कान पर चोटे आई। रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 296,115(2), 118(1), 351(2), 3(5) बीएनएस एवं इजाफा धारा 109 (1) बीएनएस का कायम कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण के आरोपी रिजवान खान उर्फ रिजु खान को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। 16 दिसंबर को आरोपी मोह. तालीफ पिता मोहम्मद शफीक, सैय्यद फरहान अली पिता सैय्यद मुब्बशर अली, शानिब उर्फ निहाल खान पिता शकील खान को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, वहीं अन्य आरोपियो की तलाश पतारसी जारी है।

युवक ने प्रेमिका के सामने खुद को आग लगाई, मौत

बैतूल। प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी प्रेमिका के सामने खुद को आग लगा ली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पार्क में हुई। मृतक की पहचान अविनाश परतेती (22 वर्ष) के रूप में हुई है, जो चटवा, जिला पांढुर्णा का निवासी था। जानकारी के अनुसार, अविनाश मंगलवार शाम अपनी प्रेमिका से मिलने घोड़ाडोंगरी पहुंचा था। जहां उसने महिला को पार्क में मिलने बुलवाया था। इसी दौरान दोनों के बीच साथ चलने को लेकर विवाद हो गया। अविनाश ने शराब के नशे में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। उसकी दोस्त वहां अकेली थी। उसने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत ही करीब 90 फीसदी जल गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को घोड़ाडोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालत गंभीर

होने पर उसे बैतूल जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि वह शादीशुदा है और मायके में रह रही है। उसका अपने पति से तलाक नहीं हुआ है। उसने कहा, अविनाश मेरा दोस्त था। उसने मुझे मिलने के लिए घोड़ाडोंगरी बुलाया। मिलने पर उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। महिला के मुताबिक उसकी शादी आठ साल पहले हुई थी। उसके पति से उसे एक बच्चा भी है, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण वह पति से अलग रह रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला के बयान के अलावा पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके जिसके कारण युवक ने यह कदम उठाया। घोड़ाडोंगरी चौकी प्रभारी आम्रपाली दहाट ने बताया कि इस मामले मर्ग डायरी मिलने के बाद जांच की जाएगी।

जल संचय अभियान के अंतर्गत आठनेर में बोरी बंधान कार्य संपन्न

बैतूल। जल संचय अभियान के अंतर्गत आठनेर विकासखण्ड में कावला सेक्टर की ग्राम पंचायत गारगुड के डंगरापाटा में खेत की नदी पर 80 बोरियों का बोरी बंधान किया गया। यह कार्य प्रस्फुटन समिति, नवांकुर संस्था, मेंटर एवं सीएमसीएलडीपी कार्यक्रम के छात्रों के संयुक्त सहयोग से सम्पन्न हुआ। बोरी बंधान कार्य में विकासखण्ड समन्वयक श्रीमती मधु चौहान, प्रस्फुटन समिति, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि सहित समिति सदस्य एवं सेक्टर के सीएमसीएलडीपी छात्र-छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता की। बोरी बंधान कार्य के पश्चात विकासखण्ड समन्वयक द्वारा उपस्थित छात्रों और समिति सदस्यों के साथ चौपाल आयोजित कर वर्षा जल संरक्षण एवं ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक बोरी बंधान निर्माण विषय पर चर्चा की गई। साथ

ही छात्रों द्वारा अपने-अपने प्रयोगशाला ग्रामों में जल संचय अभियान के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी साझा की गई।

एमपीपीएससी में चयनित जिले के श्री आकाश रघुवंशी ने सशक्त वाहनी की कक्षा में मार्गदर्शन दिया

महिला शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन एवं श्रीमति विनीता लोढ़ा जिला कार्यक्रम अधिकारीमहिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन मे प्रतियोगी परीक्षाओं कि तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग क्लास पुलिस कण्ट्रोल रूम विदिशा मे संचालित हैं। एमपीपीएससी 2024 में असिस्टेंट डायरेक्टर (वित्त विभाग) के पद पर चयनित विदिशा जिले के श्री आकाश रघुवंशी ने विदिशा में संचालित सशक्त वाहनी कि कक्षा में उपस्थित होकर अध्यनरत बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं कि तैयारी हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया।

इसके पहले महिला एवं बाल विकास विभाग के श्री संतोष रघुवंशी द्वारा श्री आकाश रघुवंशी का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया और सशक्त वाहनी की कक्षाओं के विषय मे बताया गया। आज कु कक्षा में आज 70 बालिकायें उपस्थित रहीं। श्री आकाश रघुवंशी ने बालिकाओं को मार्गदर्शित करते हुये बताया कि आप स्वयं से नोट्स तैयारी करें, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहें हैं उन परीक्षाओं के कम से कम पाँच वर्ष पहले तक के पेपर सॉल्व करें, आपकी जिस विषय मे अच्छी तैयारी है उसको कम समय देकर दुसरे विषयों पर अधिक जोर दें। श्री आकाश ने महिला शिक्षा के महत्व के बारे में बताया कि महिला शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, शिक्षा सिर्फ नौकरी का साधन नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास का साधन भी है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, समय-समय पर अभ्यास करते रहो। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं द्वारा पूछे गये प्रश्नों के आसान भाषा मे उत्तर दिये और विदिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सशक्त वाहनी की कक्षाओं कि सराहना कि गई।

विधायक डॉ चौधरी ने दो करोड़ 80 लाख रू लागत के नाली निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन

रायसेन (निप्र)। रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा गोपालपुर तिराहा से जिला जेल पठारी मार्ग की शेष राशि से नाली निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉ चौधरी ने कहा कि दो करोड़ 80 लाख रू लागत से गोपालपुर तिराहा से जिला जेल पठारी मार्ग तक नाली का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस नाली निर्माण से क्षेत्र में जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान होगा, जिससे सड़क की सुरक्षा व टिकाउपन भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने क्षेत्र में किए गए विभिन्न विकास कार्यों तथा सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया।

संक्षिप्त समाचार

सीएमएचओ ने की समन्वित गर्भपात सेवाओं की समीक्षा

सीहोर (निप्र)। जिला चिकित्सालय में सीएमएचओ डॉ. सुधीर डेहरिया द्वारा समन्वित गर्भपात सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स द्वारा इन सेवाओं के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारियों एवं स्टाफ का उन्मुखीकरण भी किया गया। समीक्षा बैठक में सीएमएचओ ने संस्थावार गर्भपात आधारित सेवाओं की समीक्षा की। डॉ डेहरिया ने निर्देश दिए कि जिस भी स्वास्थ्य संस्था में गर्भपात की सेवाऐं दी जाती हैं वहां शासन के मानदंडों का पालन किया जाए, गर्भपात सेवाओं में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान अपनी संस्था में गर्भपात सेवाएँ देने के इच्छुक मेडिकल ऑफिसर्स को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित करने के लिये लिस्ट भी तैयार की गई।

संभागायुक्त ने एसआईआर के तहत मेपिंग व सत्यापन कार्य का लिया जायजा

हरदा (निप्र)। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी सोमवार को तहसील टिमरनी के ग्राम टेमागांव के ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुंचे। यहां उन्होंने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में संलग्न सभी बीएलओ से आमने-सामने चर्चा की और मेपिंग व सत्यापन कार्य के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान कमिश्नर श्री तिवारी ने एसडीएम टिमरनी श्री संजीव नागू को निर्देश दिए कि सभी बीएलओ सत्यापन का कार्य पूर्ण करें। भ्रमण के दौरान संयुक्त आयुक्त विकास श्री जी.सी. दोहर, एसडीएम टिमरनी श्री संजीव नागू सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

संभागायुक्त श्री सिंह ने सांची में की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। भोपाल संभागायुक्त श्री संजीव सिंह द्वारा सांची में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिले में एसआईआर के तहत की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया गया। संभागायुक्त श्री सिंह ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों से कहा कि बीएलओ तथा बीएलए को समन्वय के साथ कार्य करने हेतु निर्देशित करें। बैठक में बताया गया कि एसआईआर के तहत जिले के चारों विधानसभाओं में शत-प्रतिशत कुल 1041485 गणना पत्रकों को डिजिटाइज्ड कर दिया गया है। जिले में मतदाता केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण के बारे में बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्रों की संख्या 1230 थी। इनमें 1200 से अधिक मतदाता के कारण 115 नवीन मतदान केन्द्र और दूरी अधिक होने के कारण 39 नवीन मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण किया गया हैं। इस प्रकार युक्तियुक्तकरण के पश्चात कुल 1381 मतदान केन्द्र हो गए हैं।

परिवहन विभाग के प्रवर्तन अमले को चालानी कार्रवाई के लिये मिली पीओएस मशीनें

रायसेन (निप्र)। परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत राज्य के परिवहन चेकपोस्टों को बंद कर दिया है। इनके स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एण्ड इन्फोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट जाँच का कार्य कर रहे हैं। जाँच कार्य के लिये प्रवर्तन बल(इन्फोर्समेंटफोर्स) को बॉडीवॉर्न कैमरे उपलब्ध कराये गये हैं। इन कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के माध्यम से वाहनों के विरुद्ध ऑनलाइन चालानी कार्रवाई की जा रही है। राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा ई-चेकपोस्ट मॉडल के माध्यम से ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा दी गई है। प्रवर्तन अमले द्वारा बॉडीवॉर्न कैमरे का उपयोग करने से वाहन चेकिंग के दौरान प्रत्येक कार्यवाही की मॉनीटरिंग वास्तविक समय (रियल टाइम) में कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर के माध्यम से की जा रही है। परिवहन विभाग की इस व्यवस्था से न केवल वाहन चालकों में विश्वास बढ़ा है, बल्कि वाहन चेकिंग के दौरान आने वाली अवैध वसूली की शिकायतेंभी काफी कम हो गई हैं। इस व्यवस्था से परिवहन विभाग ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इण्डिया के सपने को साकार किया है। कैशलेस चालानी कार्रवाई परिवहन विभाग के अमले को पीओएस मशीन उपलब्ध कराने से वाहनों के विरुद्ध की जाने वाली चालानी कार्रवाई को ऑनलाइन तथा कैशलेस रूप में किया जा रहा है। प्रदेश में मोटरयान परिवहन से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन पर स्व-चलित पद्धति ई-डिटेक्शन को नवम्बर-2025 से लागू कर दिया गया। फेसलेस सेवा देने के मामले में मध्यप्रदेश देश में अव्वल परिवहन विभाग की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट तथा ड्रायविंग लायसेंस आदि से संबंधित सेवाओं को एनआईसी के पोर्टल 'वाहन तथा सारथी' ऐप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इस व्यवस्था में आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सेवा प्राप्त कर पा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित फेसलेस सेवाओं की सूची में से प्रदेश में समस्त सेवाओं को फेसलेस रूप में प्रदान किये जाने से मध्यप्रदेश सम्पूर्ण देश में अव्वल देश बन गया है।

प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ता सीहोर, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन बना किसानों की समृद्धि का आधार

सीहोर (निप्र)। भारत सरकार के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (हस्स्रू) योजना देश के किसानों को रासायनिक खेती से मुक्त कर पर्यावरण-संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और लागत में कमी की दिशा में अग्रसर करने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना के अंतर्गत सीहोर जिले में अब तक 3125 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है, जो प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर जिले के किसानों की बढ़ती जागरूकता और विश्वास को दर्शाता है। योजना के तहत पंजीकृत किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने हेतु प्रति एकड़ की दर से दो वर्षों तक 4 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को प्रारंभिक सहयोग और आत्मनिर्भरता का संबल मिल रहा है।

सीहोर विकासखंड में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 10 प्रशिक्षित कृषि सखियां सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जो किसानों को जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, सोया टॉनिक, कंडा टॉनिक जैसे प्राकृतिक जैविक उत्पाद तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रही हैं। ये कृषि सखियां न केवल किसानों को इन जैविक इनपुट्स के निर्माण की तकनीक सिखा रही हैं, बल्कि किसानों के खेतों में इनके उपयोग को भी बढ़ावा देकर प्राकृतिक खेती को जमीनी स्तर पर सफल बना

रही हैं। सीहोर विकासखंड के ग्राम सागोनी निवासी किसान श्री चंदरसिंह धनगर इस योजना की सफलता का एक प्रेरणादायी उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में वे रासायनिक खेती करते थे, जिसमें लागत अत्यधिक थी और भूमि का स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा था।

इसी दौरान क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी की सलाह पर उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने का निर्णय लिया। इसके पश्चात आत्मा योजना के अंतर्गत बीटीएम श्री संदीप पाटील के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना पंजीयन कराया और प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। किसान श्री धनगर ने बताया कि वर्तमान में प्राकृतिक खेती अपनाने से उनकी खेती की लागत में कमी आई है तथा भूमि की भौतिक संरचना और उर्वरता में भी सुधार हुआ है। आज वे कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ खेती के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, बल्कि भूमि और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी को भी मजबूत किया है। किसान श्री धनगर ने कहा है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना केवल जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार और किसानों के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य कर रही है। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत कृषि विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है। सीहोर जिला प्रशासन के सतत मार्गदर्शन और सहयोग से यह योजना जिले में तेजी से सफलता की नई कहानियां गढ़ रही है और आने वाले समय में सीहोर को प्राकृतिक खेती के एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

सीहोर जिला प्रशासन द्वारा की गई है हाट बाजार लगाने की पहल

किसान श्री धनगर ने यह भी बताया कि सीहोर जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में किसानों के जैविक उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध कराने हेतु सीहोर के बाल विहार मैदान में प्रत्येक रविवार को जैविक हाट बाजार लगाने की अभिनव पहल की गई है। यह पहल हम जैसे किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि यहां हम अपने जैविक कृषि उत्पादों का सीधे विक्रय कर सकते हैं और हमें उनके उचित मूल्य भी प्राप्त होंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को भी मिलावट रहित, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे किसान और उपभोक्ता के बीच सीधा और भरोसेमंद संबंध स्थापित होगा।

रात्रि गश्ती के दौरान वन विभाग की टीम ने की कार्यवाही

विदिशा (निप्र)। वन मण्डलाधिकारी, श्री हेमन्त यादव के निर्देशन में की जा रही रात्रि गश्ती के दौरान मुखबिर की सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी लटेरी (दक्षिण) श्री विवेक चैधरी द्वारा टीम गठित कर परिक्षेत्र सहायक चैपड़ा श्री संजय कुमार मीना, का.वा.वनपाल, बीटगार्ड मुस्करा श्री अमित शर्मा एवं अन्य स्टाफ को लटेरी-शमशाबाद रोड से लगे वनक्षेत्र बीट मुस्करा के वनक्षेत्र में दबिश देने हेतु भेजा गया। गश्ती करते हुये स्टाफ ने बीट मुस्करा के कक्ष क्र. पी-302 से एक मोटर सायकल को निकलकर लटेरी-शमशाबाद रोड की ओर आते हुये देखा, उनको रोककर जांमें मोटर सायकल चालक के पास एक थैली में चाकू जिसकी पैमाइस करने पर 14 से.मी. एवं पीछे बैठे व्यक्ति से एक एयरगन बंदूक जिसमें टेलीस्कोप लगा पाया गया। दोनों से पूछ-ताछ करने पर उनके द्वारा शिकार करने के इरादे से आना स्वीकार किया है। गिरफ्तार किये गए आरोपी गुफरान अहमद पुत्र जहूर अहमद, निवासी करोद, भोपाल और मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद अफरोज, निवासी म.नं. 344 पुलिस स्टेशन के सामने, श्यामला हिल्स, तहसील हुजूर भोपाल हैं।दोनों को गिरफ्तार कर एक मोटर सायकल हीरो एच.एफ. डीलक्स जिसका वाहन नं. एमपी 40 एमएस1768 सहित जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्र. 24ध्83 दिनांक 15.12.2025 में जारी किया गया।

ग्रामीण स्तर पर फसल बीमा पाठशाला का आयोजन

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में फसल बीमा पाठशाला सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत आज सोमवार को कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड नटेरन के ग्राम चक्क विलास में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। एसबीआई जनरल से नटेरन तहसील समन्वयक श्री शुभम मीणा द्वारा फसल बीमा पाठशाला सप्ताह के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई।

फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ

बीमा योजना के उद्देश्य, लाभ, पंजीयन प्रक्रिया, दावा प्रकरण एवं जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर कृषकों को विस्तार से समझाया गया। कृषक एप्लीकेशन ऐप भी डाउनलोड कराई गई, साथ ही किसानों को समय पर बीमा कराने एवं प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित नुकसान से बचाव हेतु आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया कार्यक्रम में कृषि विस्तार अधिकारी सुश्री संगम रघुवंशी, आत्मा परियोजना से श्री अनिकेत रघुवंशी, श्रीमती रागिनी अहिरवार उपस्थित रहे।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाड़ी में कार्यशाला सम्पन्न

विद्यार्थियों को पॉस्को एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम आदि की दी गई जानकारी

रायसेन (निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सोमवार को बाड़ी में पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी एवं शासकीय संदीपनी विद्यालय बाड़ी में मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित की गई। जिसमें एक हजार से अधिक विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बाल विवाह मुक्त अभियान अंतर्गत 100 दिवसीय गतिविधियों की जानकारी बालकों को प्रदान की गई एवं बाल विवाहमुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। प्रशिक्षण में बाल संरक्षण अधिकारी दिनेश मालवीय द्वारा नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। बालकों को नशे से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत समस्त बालकों को शपथ दिलाई गई। परियोजना अधिकारी जुलैखा खान द्वारा विद्यार्थियों को पोषण के संबंध में जानकारी प्रदान की गई एवं बालिकाओं को एनीमिया के कारण होने वाली बीमारियों के संबंध में जानकारी दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं की शिक्षा, स्वरोजगार एवं स्वागम लक्ष्मी योजना की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य निशांत तिवारी एवं शासकीय संदीपनी विद्यालय बाड़ी की प्राचार्य सुमन तिवारी उपस्थित रहीं।

संयुक्त बैठक में सभापति ने शासन की योजनाओं की उपलब्धि की अधिकारियों से की चर्चा

नर्मदापुरम (निप्र)। जिला प्रशिक्षण केंद्र नर्मदापुरम में स्वास्थ्य, महिला बाल विकास एवं आयुष विभाग की संयुक्त बैठक सभापति ज्योत्सना पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला समिति सदस्य उमेश यादव, ब्रजकिशोर पटेल उपस्थित रहे।

सीएमएचओ डॉ नरसिंह गेहलोत ने विभाग की आयुष्मान भारत योजना, 70 प्लस आयु वाले नागरिकों के लिए आयुष्मान योजना, क्षय उन्मूलन, मलेरिया, सिकल सेल स्क्रीनिंग, टीकाकरण सहित अन्य सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की लक्ष्य उपलब्धि की जानकारी दी।

सिविल सर्जन डॉ सुनीता कामले ने आईसीयू जल्द शुरू होने की जानकारी दी। डीपीओ ललित डेहरिया ने लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, पोषण आहार एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारी दी। जिला आयुष अधिकारी डॉ श्रीराम करोंजिया द्वारा विकासखंडों में आयुष विभाग के चिकित्सकों एवं स्टॉफ द्वारा

आमजन को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। बैठक में डीएचओ डॉ सृजन सेंगर, आरएमओ डॉ गजेंद्र यादव, जिला मलेरिया अधिकारी अरुण श्रीवास्तव, जिला मीडिया प्रभारी सुनील साहू, डीसीएम शैलेन्द्र शुक्ला, डीपीएम कविता भोई, इंजीनियर मयूरी जैन ने अपने अपने संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। समिति सदस्य उमेश यादव द्वारा एएनएम के रिक्त पदों को शीघ्र पूर्ण करने, पोस्ट मार्टम गृह के पास व्यवस्था दुरुस्त करने की चर्चा सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन से की। बैठक में एएसओ राजेश अहिरवार, हेमंत पटेल, मदन वर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुशासन सप्ताह की सभी तैयारी समय पर पूरी की जाए : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना

नर्मदापुरम (निप्र)। पिछले एक सप्ताह में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समाधान में अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए जाएं। सुशासन सप्ताह के संबंध में संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर अभियान की रूपरेखा स्पस्ट की जाए। न्यायालय एवं आयोग से प्राप्त सभी प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों द्वारा समय सीमा का ध्यान रखते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। एसडीएम एवं अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारी फील्ड स्तर पर दिखाएं अधिक सक्रियता। परिवर्तक अधिकारियों द्वारा बताई गई समस्यों पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर समस्या का समाधान सुनिश्चित करे संबंधित विभाग प्रमुख। 26 से 29 दिसंबर तक लगने वाले पचमढ़ी महोत्सव मेले की सभी तैयारियां सुनियोजित ढंग से पूर्ण की जाए। समय सीमा की

बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने उक्त निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर ने निर्देश दिए की बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के संबंध में की गई कार्यवाहियों का पालन प्रतिवेदन भी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने पिछले एक सप्ताह में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समाधान में अपेक्षित प्रगति दर्ज न करने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए की पिछले एक सप्ताह में अपेक्षित प्रगति दर्ज न करने वाले अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी किए जाएं तथा पूर्व में जारी किए गए नोटिस के जवाब संतोषपरक ना पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं। कलेक्टर ने विभागों की खराब रैंकिंग एवं ग्रेडिंग पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर विभागीय रैंकिंग एवं ग्रेडिंग अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य को दर्शाता है। उन्होंने सिंचाई विभाग की बढ़ती हुई शिकायतों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा शिकायतों की बढ़ती संख्या यह स्पष्ट करती है कि विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर कार्य में शिथिलता बरती जा रही है। जो की कतई स्वीकार्य नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह में शिकायतों के निराकरण में गति लाएं।

इसी प्रकार उन्होंने नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व सामाजिक न्याय विभाग, संस्थागत वित्त सहित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की शिकायतों के समाधान में अपेक्षाकृत प्रगति प्राप्त करें। कलेक्टर ने राजस्व विभाग अंतर्गत 300 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए की एक सप्ताह में उक्त शिकायतों को संतोषजनक रूप से बंद किया जाना सुनिश्चित करें। शिकायतों के बंद न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। कलेक्टर सुश्री मीना ने समाधान ऑनलाइन के तहत चिन्हित बिंदुओं से संबंधित शिकायतों पर सतत मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए की समाधान ऑनलाइन के तहत चिन्हित किए गए बिंदुओं से संबंधित शिकायतों में कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार से सुस्ती ना दिखाएं। शिकायतों में त्वरित संज्ञान लेते हुए उनका निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए की 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह अंतर्गत प्रारंभ हो रहे प्रशासन गांव की ओर अभियान की सभी तैयारियां निर्धारित समय अवधि में पूरी की जाए तथा अभियान की सतत समीक्षा करते हुए इस अवधी में अभियान मोड में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया कि अभियान संबंधी निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए जाएं।

राइट क्लिक

मैसी के भारत दौरे से आखिर किस चीज का प्रमोशन हुआ?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी के ताजा भारत दौरे और उन्हें देखने के लिए जुटी भारतीयों की भीड़ से इतना ही साबित हुआ कि दुनिया के लिए हम भारतीयों का मतलब सच्चे खेल प्रशंसक से ज्यादा एक भीड़ है और भारत एक विशाल बाजार है, जिसका जो जब चाहे, जैसा चाहे दोहन कर सकता है। हम भी मैसी जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी तैयार करने की जगह विदेशी खिलाड़ियों की आरती उतारकर ही खुश हैं। भारत के पांच शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और जामनगर के अपने सद्भावना दौरे के समापन के बाद लियोनेल मैसी ने भले ही भारत को अपनी शानदार मेहमानवाजी और प्यार के लिए 'थैंक्यू' कहा हो, लेकिन ये दौरा हमे आत्ममंथन पर विवश करता है। क्योंकि इस दौरे से आखिर किस चीज का प्रमोशन हुआ? कई नामी भारतीय खिलाड़ियों ने भी ऐसे प्रायोजित दौरे के औचित्य पर सवाल उठाए हैं कि आखिर इस दौरे से भारत को हासिल क्या हुआ, सिवाय एक भव्य तमाशे के?

मैसी का यह दौरा कोलकाता के एक खेल प्रशंसक और इवेंट कंपनी के मालिक शतद्रु (सतलुज नदी का प्राचीन नाम) दत्ता ने आयोजित किया था। अड़तीस वर्षीय मैसी अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी को पहली बार एमएलएस कप जिताने में मदद करने के बाद प्रमोशनल दौरे पर निकले हैं। इस दौरे को GOAT इंडिया 2025 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। GOAT यानी ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। कोलकाता के अलावा मैसी के इस दौरे में सम्बन्धित राज्यों की सरकारों की भी भागीदारी रही। हैदराबाद में मेसी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ एक प्रदर्शन मैच खेला और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की तो मुंबई में मैसी ने महाराष्ट्र सरकार के 'प्रोजेक्ट महादेव' का शुभारंभ किया। जिसका उद्देश्य राज्य में जमीनी स्तर पर फुटबॉल को मजबूत करना है। दिल्ली में उनके साथ फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी थे। तीनों ने आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली से मुलाकात की। जय शाह ने उन्हें टी 20 विश्वकप में आने का न्यौता भी दिया। भारत में मैसी 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंडुलकर और भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री से भी मिले। दौरे के आखिर में वो जामनगर में अंबानी के निजी चिड़ियाघर वनतारा भी गए और प्राणियों को देखा। लेकिन मैसी के दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा देश में फुटबॉल की राजधानी' कहे जाने वाले कोलकाता में हुए भारी हंगामे की हुई। जहां मैसी से समुचित मुलाकात न कराए जाने पर दर्शकों ने गुस्सा जताया और भारी तोड़फोड़ की। दर्शकों का आरोप है कि आयोजकों ने मैसी से मुलाकात के नाम पर उन्हें साफ तौर पर ठगा है। साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम का टिकट 4300 रू. का था, जिसे 50 हजार से ज्यादा लोगों ने 25 रू. हजार रू. तक में ब्लैक में खरीदा। बदले में मैसी 10 मिनट के लिए आए और हाथ हिलाकर चले गए। कोलकाता में इस बवाल के राजनीतिक परिणामों को भांपकर और राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी ने ताबड़तोड़ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी तथा राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास से इस्तीफा ले लिया। उधर आयोजक शतद्रु धोखाधड़ी के मामले में 14 दिन की पुलिस हिरासत में हैं। लेकिन मैसी के दौरे के पीछे मकसद क्या था? क्या यह भारत में फुटबॉल को नए सिरे से लोकप्रिय बनाने के कैम्पेन का हिस्सा है या फिर 'ग्रेट प्लेयर टूरिज्म' का नया चोंचला है अथवा नामी खिलाड़ियों को भारत दर्शन करवाकर भारतीयों की जेब ढीली करवाने का नया पैंतरा है? GOAT दौरे के आयोजक शतद्रु दत्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं और खेलों के रसिया हैं। ऐसे आयोजन पहले भी करते रहे हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली के करीबी हैं। शतद्रु की अपनी सम्पत्ति का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैसी के इस दौरे में अरबों के वारे-न्यारे हुए हैं, इसमें संदेह नहीं।

यूं भारत में फुटबॉल का इतिहास डेढ़ सौ साल से ज्यादा पुराना है। देश में पहला फुटबॉल क्लब 1872 कोलकाता में रजिस्टर्ड हुआ था। लेकिन देश में फुटबॉल का विकास और प्रगति उस तरह से कभी नहीं हुई, जैसी कि अपेक्षित थी। 1948 के लंदन ओलम्पिक भारतीय फुटबॉल टीम नंगे पैर ही मैदान में उतरी थी, क्योंकि उसके पास जरूरी जूते ही नहीं थे। इसके बाद टीम पर बैन लगा दिया गया था। भारत में फुटबॉल लोकप्रिय खेल है। देश में 122 फुटबॉल स्टेडियम भी हैं, लेकिन खेल का स्तर बहुत ही नीचा है। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का नंबर दुनिया में 142 वां है। भारतीय टीम फीफा कप तो क्या एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती। GOAT इंडिया के आयोजन पर कुल कितने रू. खर्च हुए यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फुटबॉल प्रेमियों को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत सरकार ने देश में फुटबॉल के लिए पिछले साल बजट में 8.78 करोड़ रू. दिए थे। और अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन उसमें भी केवल 4 करोड़ रू. साल भर में खर्च कर सका था। जबकि GOAT दौरे में इससे कई गुना ज्यादा खर्च हो गए।

इसमें दो राय नहीं कि लियोनेल मैसी दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से हैं। वो अब तक 46 टीम ट्रॉफियां जिता चुके हैं। 600 मिलियन डॉलर की सम्पत्ति के मालिक मैस्सी एक परोपकारी भी हैं और अर्जेंटीना में अपने पिता के साथ टैक्स फ्रॉड के मामले में भी फंस चुके हैं। बेहतर होता कि मैसी के नाम पर महंगा तमाशा करने की जगह इतना पैसा भारत में फुटबॉल के जमीनी स्तर पर विकास और विस्तार पर खर्च किया जाता। क्रिकेट की तर्ज पर एक व्यापक फुटबॉल नेटवर्क खड़ा कर ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशकर उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल करने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाता। गांव-गांव में फुटबॉल क्लब और अकादमियां खड़ी कर ग्रामीण स्तर से राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल टूनामेंट आयोजित किए जाते। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है, वो नाकाफी है।

मैसी के इस प्रायोजित दौरे की कई नामी भारतीय खिलाड़ियों ने आलोचना की है। भारत के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा ने सवाल किया कि क्या एक समाज के तौर पर हम खेल संस्कृति बना रहे हैं या फिर किसी दूसरे देश की खेल शख्सियत का उत्सव मना रहे हैं? मैसी का जयगान करने के बाद अब समय आत्मनिरीक्षण का है। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि 'मैं उम्मीद करती हूं कि कोई तो वक्त आएगा, जब सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हर दिन के लिए हम सचमुच खेल के लिए जाग सकेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया ने भी कोलकाता के आयोजन की कड़ी आलोचना की है। सवाल यह भी है कि हमने भले मैसी को भारत बुला लिया हो, लेकिन अर्जेंटीना ने कभी किसी नामी भारतीय खिलाड़ी को इस तरह बुलाकर सम्मानित किया? क्रिकेट वहां खेला नहीं जाता, लेकिन क्या कोई भारतीय हॉकी अथवा अन्य खिलाड़ी भी इस लायक नहीं समझा गया? दरअसल जहां वैश्विक स्तर के खिलाड़ियों की फसल तैयार की जाती है, वहां ऐसे तमाशों की जगह ठोस काम ज्यादा होता है और वहां की जनता भी तमाशबीन बनने की जगह नायकों को पैदा करने में भरोसा करती है। बेहतर तो यह होता कि मैसी जैसा कोई शानदार खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए कोच और मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया जाता।

रतलाम के जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

- **कहा-पारिवारिक और विधानसभा क्षेत्र के दायित्व निभाने के कारण काम नहीं कर पा रहा**

भोपाल (नप्र)। आलीराजपुर के बाद रतलाम ग्रामीण के जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पारिवारिक और विधानसभा क्षेत्र के दायित्व के निर्वहन के कारण वे काम नहीं कर पा रहे हैं। जीतू पटवारी दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके करीब 18 महीने बाद अगस्त 2025 में उन्होंने 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा की थी। इसमें हर्ष विजय गहलोत का भी नाम शामिल है। उन्हें पहले से रिक्त रतलाम ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया था। नियुक्ति के करीब 4 महीने बाद ही गहलोत ने पद से इस्तीफा दे दिया। 6 दिसंबर को आलीराजपुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश पटेल ने इस्तीफा दे दिया था।

बीजेपी कार्यालय घेरने निकले कांग्रेसी गिरफ्तार

भोपाल (नप्र)। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया है, जिससे कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी राहत मिली है। इसी फैसले के बाद राजधानी भोपाल में कांग्रेसी बुधवार को बीजेपी कार्यालय का घेराव करने निकले। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का प्रयोग किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता वॉटर कैनन के प्रेशर से सड़क पर गिरकर चोटिल हुए। मौके पर जीतू पटवारी और भोपाल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस भी हुई। इसके बाद पुलिस ने धक्का-मुक्की कर कार्यकर्ताओं को बसों में बैठाकर ले गई। इस दौरान पीसीसी चीफ पटवारी के इशारे में कांग्रेसियों ने पुलिस की बस का घेराव कर दिया। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी, भोपाल शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, ग्रामीण अध्यक्ष अनोखी पटेल, पूर्व मंत्री पीपी शर्मा, गोविंदपुर के पूर्व प्रत्याशी रविंद्र साहू, मनोज शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।

कोर्ट ने क्या निर्णय सुनाया

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि यह किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एसआईआर) पर आधारित नहीं थी। कोर्ट के अनुसार धारा 3 और 4 के तहत धनशोधन के आरोप तभी देखे जा सकते हैं जब मामले का आधार एक वैध एफआईआर हो। इसीलिए अदालत ने ईडी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी की दलीलें कानून के अनुरूप नहीं थीं और प्रचलित नियमों के अनुसार मुकदमे का आधार मजबूत नहीं माना जा सकता। इसी वजह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को खारिज कर दिया गया।